●वर्ष-5
●अंक-246
रायपुर, रविवार
31 मई 2026
●पृष्ठ-8
●मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8> तंबाकू मुक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण में...

आईएसआई के आठ आतंकी गिरफ्तार

विस्फोटक बरामदः निशाने पर थे न्यूक्लियर प्लांट-एयरपोर्ट-रेलवे स्टेशन

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (विशेष प्रकोष्ठ) ने दिल्ली, मुंबई, पंजाब व चंडीगढ़ में बड़ी हमलों की साजिश को नाकाम कर दिया है। स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाक-मुंबई अंडरवर्ल्ड-पाकिस्तान गैंगस्टर शहजाद भट्टी के आतंकी माड्यूल का पर्दाफाश करते हुए आठ संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है।

पूरे देश में फैला चुका नेटवर्क

ये मॉड्यूल पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी, मुन्ना झिंगाड़ा और यावर खान के इशारे पर काम कर रहे थे। इस मॉड्यूल का नेटवर्क पूरे देश में फैल चुका था। पाक आईएसआई-मुंबई अंडरवर्ल्ड-पाक नेटवर्क ने दिल्ली और अन्य शहरों में महत्वपूर्ण ठिकानों, सुरक्षा प्रतिष्ठानों और पुलिस कर्मियों पर ग्रेनेड हमले, टॉरगेट किलिंग और गोलीबारी कर बड़ी आतंकी हमले करने की साजिश थी।

हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल बरामद

दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त (स्पेशल सेल) अनिल शुक्ला ने बताया कि दिल्ली से गिरफ्तार किए

गए तीन गुर्गों के पास से पाकिस्तान में बने चार हैंड ग्रेनेड, दो ग्लॉक पिस्तौल और 24 कारतूस बरामद किए गए हैं। विशेष पुलिस आयुक्त शुक्ला ने बताया कि सेल के नई दिल्ली रेंज के पुलिस उपायुक्त प्रवीण कुमार त्रिपाठी की देखरेख में एसीपी विवेक कुमार त्यागी, इंस्पेक्टर सुनील राजैन और इंस्पेक्टर धीरज महलावत की टीम ने इस पाक आईएसआई-मुंबई अंडरवर्ल्ड और शहजाद भट्टी के एक अंतरराष्ट्रीय और अंतर-राज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों के खिलाफ स्पेशल सेल, नई दिल्ली पुलिस स्टेशन द्वारा बीएनएस और यूएपीए की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

अलग-अलग जगह से गिरफ्तार

विशेष पुलिस उपायुक्त ने बताया कि खुफिया इनपुट, तकनीकी विश्लेषण तथा मानवीय स्रोतों से मिली मिली जानकारी के बाद आरोपी यूपी निवासी विजय उर्फ शूटर को 14 मई को पुणे से गिरफ्तार किया गया। उसके साथी नीतीश को 17 मई को साहिबगंज, झारखंड से गिरफ्तार किया गया। विजय से पूछताछ और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर 27 मई को मुंबई से तौकीर और अरबाज को गिरफ्तार किया गया। मुंबई स्थित आरोपियों से पूछताछ के बाद पंजाब से एक और समूह, उन्हीं हैंडलरों के इशारे पर, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले करने के लिए दिल्ली आ रहा है। तीनों आरोपी हरविंदर सिंह, गगनदीप सिंह और मनजीत सिंह 30 मई को लगभग 01ः00 बजे महरौली-बदरपुर रोड से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया। तीनों ही पंजाब के रहने वाले हैं। इससे पूछताछ के बाद पंजाब के तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद एक नेपाली नागरिक अंग कामी लामा को गिरफ्तार किया गया। उसे मुन्ना झिंगाड़ा के निर्देश पर दिल्ली में आरोपियों के लिए छिपने की जगह का इंतजाम करने और उनकी गतिविधियों के लिए पैसे मुहैया कराने का काम सौंपा गया था।

इनको ये काम सौंपा गया था

विजय, पाकिस्तान और दुबई से संचालित हो रहे शहजाद भट्टी नेटवर्क के सदस्यों के साथ नियमित संपर्क में था। विजय को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में विभिन्न आपराधिक और आतंकी गतिविधियां अंजाम देने का काम सौंपा गया था। उसे दिल्ली-एनसीआर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवाओं की भर्ती करने का काम भी सौंपा गया था। तौकीर और अरबाज को दोनों आईएसआई हैंडलर यावर खान और मुन्ना झिंगाड़ा के संपर्क में थे। इनकी भर्ती मुंबई के एक हुजैफा (फरार) ने की थी, जो शहजाद भट्टी, यावर और मुन्ना के इशारे पर काम कर रहा था। इन्हें दिल्ली और मुंबई में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, सुरक्षा संस्थानों और पुलिस कर्मियों पर ग्रेनेड हमले और गोलीबारी करने का काम सौंपा गया था।

कॉकरोच जनता पार्टी विवाद पर आरएसएस ने दी प्रतिक्रिया

लोकतंत्र में हर आवाज के लिए है जगहः आंबेकर

नागपुर। सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनी 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) को लेकर चल रहे विवाद के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पहली बार प्रतिक्रिया सामने आई है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने यहां मीडिया से बात करते हुए कहा, लोकतंत्र में विभिन्न विचारों, मतों और सार्वजनिक चर्चाओं के लिए पर्याप्त स्थान होता है तथा ऐसी गतिविधियों को चिंता या असामान्य स्थिति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

इसी के साथ ही आंबेकर ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में हर प्रकार की आवाज और भावना को समाहित करने की क्षमता मौजूद है। उन्होंने कहा कि देश में पारदर्शी चुनाव, स्वतंत्र मीडिया और सोशल मीडिया जैसे मजबूत मंच उपलब्ध हैं, जहां प्रतिदिन विभिन्न मुद्दों पर खुली चर्चा होती है। ऐसे में किसी भी नए विचार, आलोचना या व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा माना जाना चाहिए। यह बयान

ऐसे समय में आया है जब सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हो रहे सीजेपी को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विशेष रूप से युवाओं और जेन-जी वर्ग के बीच इस व्यंग्यात्मक मंच की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स की संख्या कई प्रमुख राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया खातों से भी अधिक हो गई है।

कुछ भाजपा नेताओं ने इस मंच के उद्देश्यों और गतिविधियों पर सवाल उठाए हैं तथा इसके कथित विदेशी संबंधों को लेकर भी आरोप लगाए हैं। वहीं, सरकार द्वारा सीजेपी के एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के बाद मामला न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंच गया है और फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

संघ को हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं

संघ प्रचारक आंबेकर ने यह भी कहा कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं, राजनीतिक दल और मीडिया ऐसे मुद्दों से निपटने में पूरी तरह सक्षम हैं। उनके अनुसार संघ को हर विवाद में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। आंबेकर ने देश के युवाओं पर भरोसा जताते हुए कहा कि नई पीढ़ी भारत के भविष्य को लेकर आशावान है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी युवा शक्ति की क्षमता और समझ पर पूरा विश्वास रखता है।

उधर, विपक्ष के कई नेताओं और मनोरंजन जगत की कुछ हस्तियों ने भी सीजेपी के समर्थन में अपनी राय व्यक्त की है, जिससे यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित गुरुद्वारा परिसर में छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज द्वारा आयोजित विशाल छबील एवं छायाचित्र प्रदर्शनी में शामिल होकर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। (विस्तृत समाचार पेज 8 पर)

डीके शिवकुमार कर्नाटक के 24 वें मुख्यमंत्री

नईदिल्ली। विधानसभा सौधा में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में डीके शिवकुमार को औपचारिक रूप से कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) का नेता चुना गया और उम्मीद है कि वे 3 जून को कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक में सीएलपी सचिव अल्लमप्रभु पाटिल, कर्नाटक के प्रभारी एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल उपस्थित थे। निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जिन्होंने 28 मई को इस्तीफा दिया था, ने डीके शिवकुमार को अगले सीएलपी नेता के रूप में प्रस्तावित और घोषित किया।

शिवकुमार के सीएलपी नेता चुने जाने

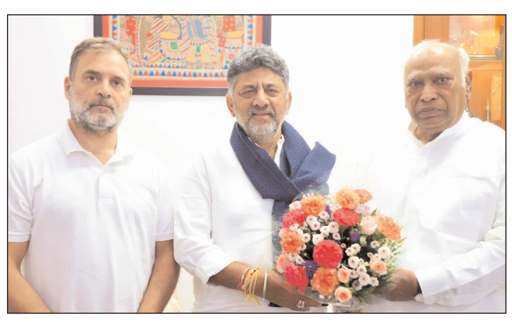

की पुष्टि करने वाला आधिकारिक पत्र लोक भवन भेजा जाएगा, और उसके बाद वे राज्यपाल से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शिवकुमार ने पहले कहा था कि शपथ ग्रहण समारोह 3 जून को होगा। गुरुवार को सिद्धारमैया ने राज्यपाल कार्यालय में अपना इस्तीफा सौंप दिया और कहा कि वह पार्टी नेतृत्व के निर्णय के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। बाद में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, जिससे कर्नाटक के नेतृत्व में संभावित परिवर्तन को लेकर महीनों से चल रही अटकलों का अंत हो गया।

अगले दिन, राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की तैयारियों के बीच उन्होंने नई दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की। खबरों के अनुसार, सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें सूचित किया कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व के निर्देशानुसार पद से इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया।

यह बैठक नई दिल्ली में कांग्रेस हाई कमांड, सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच हुई विचार-विमर्श की बैठक के बाद हुई, जिसका उद्देश्य नेतृत्व परिवर्तन को अंतिम रूप देना और नई सरकार के गठन की दिशा तय करना था।देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें ह्रह्नह्वद्धह्वठ्ठह्यद्ध ह्नद्ग2ह्य द्वह्व ।।द्धह्वस्रह्य केवल प्रभासाक्षी पर।

प्रमुख समाचार

20 जून से पहले मोदी कैबिनेट का विस्तार संभव

नईदिल्ली। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले विस्तार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नौ जून को इस कार्यकाल के दो साल पूरा होने और 10 जून को राजग शासित दलों के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक के बाद पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उसके बाद भाजपा के केंद्रीय संगठन की नई टीम बनेगी। हाल ही में दिल्ली के अध्यक्ष बनाए गए हर्ष मल्होत्रा और चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी संगठन पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। सूत्रों ने बताया कि विस्तार के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम पर साथ-साथ मंथन हो रहा है। संकेत हैं कि मुख्यमंत्री परिषद की बैठक के बाद 20 जून से पहले मंत्रिमंडल विस्तार को अमली जामा पहनाया जाएगा, इसके तत्काल बाद केंद्रीय संगठन की नई टीम घोषित कर दी जाएगी। केंद्रीय संगठन की नई टीम और मंत्रिमंडल विस्तार से बनने वाली पीएम मोदी की नई टीम में आगामी आम चुनाव तक कोई बदलाव नहीं होना है।

सेवानिवृत्त हुए सीडीएस जनरल अनिल चौहान

नई दिल्ली। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान शनिवार को सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर नई दिल्ली में उन्हें भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की ओर से संयुक्त रूप से गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। यह समारोह उनके चार दशक से अधिक लंबे और गौरवशाली सैन्य जीवन के सम्मान में आयोजित किया गया। सेवानिवृत्ति के अवसर पर जनरल चौहान ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद आयोजित समारोह में तीनों सेनाओं के जवानों ने उन्हें औपचारिक सलामी दी। इस मौके पर जनरल चौहान ने कहा कि तीनों सेनाओं के संयुक्त गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवा से विदाई लेना उनके लिए गर्व और सम्मान का विषय है। उन्होंने अपने सैन्य जीवन के दौरान मिले सहयोग और विश्वास के लिए सशस्त्र बलों तथा देशवासियों का आभार व्यक्त किया।

बंगाल में लागू होगी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार जल्द ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को कोलकाता में स्वास्थ्य विभाग के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 2,103 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिनमें से 527 करोड़ रुपये की पहली किस्त राज्य को मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि इस राशि से राज्यभर में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अधिकारी ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.36 करोड़ से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। इससे बड़ी संख्या में लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने बताया कि जिला अस्पतालों की निगरानी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए राज्यभर में कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जा रहे हैं।

बिहार सरकार पुलिस बुला लें, बंगला नहीं छोड़ूंगी : राबड़ी देवी

पटना। आरजेडी नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने शनिवार को घोषणा की कि बिहार सरकार द्वारा उन्हें परिसर खाली करने का आदेश दिए जाने के बाद, वह पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित अपने सरकारी आवास को नहीं छोड़ेंगी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि वे जगह खाली कराने के लिए पुलिस को बुला सकते हैं, लेकिन मैं जगह खाली नहीं करूंगी। बिहार सरकार ने शुक्रवार को बेदखली का नोटिस जारी किया, जिसमें बताया गया कि बंगला बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। सरकारी सूचना में यह भी बताया गया कि राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता होने के नाते पहले ही वैकल्पिक सरकारी आवास आवंटित किया जा चुका था, लेकिन उन्होंने अभी तक 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली नहीं किया है। 25 नवंबर, 2025 के विभागीय आदेश द्वारा हार्डिंग स्थित मकान संख्या, दूसरी मंजिल, राबड़ी देवी को आवंटित किया गया था।

अभिषेक बनर्जी के आवास पर फिर पहुंची सीआईडी की टीम

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल सीआईडी ने नोटिस जारी कर 1 जून को दोपहर 12 बजे भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है। शनिवार को सीआईडी की पांच सदस्यीय टीम कोलकाता के कालीघाट स्थित उनके आवास पहुंची और उन्हें नोटिस सौंपा। नोटिस मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सीआईडी अधिकारियों को नोटिस व्यक्तिगत रूप से देना था, इसलिए वे उनके आवास पर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, उन्हें नोटिस देना था और मुझे उसे व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करना था। वे पहले किसी और जगह चले गए थे, क्योंकि उन्हें मेरे आवास की सही जानकारी नहीं थी। अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए बनर्जी ने कहा कि उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वे झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, पहले सिर्फ ईडी और सीबीआई थीं, अब बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस और केएमसी भी शामिल हो गए हैं।

किसानों के लिए कुछ भी कर जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी

नीरज कुमार दुबे

किसानों के हितों की रक्षा और देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाए रखना मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट मानना है कि किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, इसलिए जरूरत पड़ने पर सरकार इसके लिए खजाना खोलने से भी पीछे नहीं हटती। हम आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर खाद की आपूर्ति और कीमतों पर दबाव बढ़ा है, लेकिन केंद्र सरकार ने समय रहते कई महत्वपूर्ण कदम उठाकर यह सुनिश्चित करने की तैयारी शुरू कर दी है कि खरीफ और रबी मौसम में किसानों को खाद की कमी का सामना न करना पड़े। वैकल्पिक परिवहन मार्गों की तलाश, अतिरिक्त आयात, बढ़ती सब्सिडी का बोझ उठाने की तैयारी और सक्रिय कूटनीतिक प्रयास इस बात का प्रमाण हैं कि किसानों की जरूरतों को पूरा करना सरकार की सबसे बड़ी चिंता है।

रिपोर्टों के मुताबिक, पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद भारत आने वाले खाद से लदे 17 जहाज फारस की खाड़ी क्षेत्र में फंस गए हैं। इन जहाजों के अटकने से देश में खाद आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका पैदा हो गई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक वैकल्पिक योजना पर काम शुरू किया है। इसके तहत संबंधित बंदरगाहों पर जहाजों के पहुंचने के बाद खाद को सड़क मार्ग से लगभग 1200 किलोमीटर दूर सऊदी अरब के यनबू बंदरगाह तक पहुंचाया जाएगा। वहां से इसे फिर समुद्री मार्ग के जरिए भारतीय बंदरगाहों तक लाने की योजना बनाई जा रही

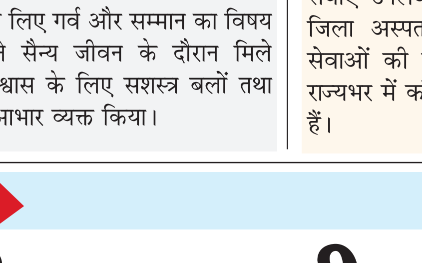

है। यद्यपि यह मार्ग लंबा है और इसमें अधिक समय लगेगा, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इसे सबसे व्यवहारिक विकल्प माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार खाद विभाग ने मंत्रियों के एक अनौपचारिक समूह को इस योजना की जानकारी दी है। अधिकारियों का मानना है कि जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित होने के कारण सीधे मार्ग से आपूर्ति फिलहाल संभव नहीं है। देरी के कारण 60 से 70 दिनों तक अतिरिक्त समय लग सकता है, जिससे लागत भी बढ़ेगी। हालांकि सरकार का मानना है कि खरीफ मौसम के दौरान किसानों को खाद की उपलब्धता बनाए रखने के लिए यह अतिरिक्त प्रयास जरूरी है। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया है कि यदि संघर्ष लंबा खिंचता है तो इसका असर रबी फसलों की बुआई पर भी पड़ सकता है।

इसी चुनौती से निपटने के लिए भारत ने खाद आयात की दिशा में भी बड़े कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार ने 17 लाख टन यूरिया के आयात के लिए नया वैश्विक निविदा आमंत्रित किया है। सरकारी क्षेत्र की राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने पश्चिमी और पूर्वी तटों के लिए अलग-अलग मात्रा में आयात प्रस्ताव मांगे हैं। इन खेपों को जुलाई के तीसरे सप्ताह तक रवाना करने की योजना बनाई गई है, ताकि धान, मक्का और सोयाबीन जैसी प्रमुख खरीफ फसलों की बुआई से पहले पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जा सके हम आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया आयातक देश है और ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया का संघर्ष प्राकृतिक गैस तथा अमोनिया जैसी प्रमुख कच्ची सामग्रियों की आपूर्ति को प्रभावित कर रहा है, तब मोदी सरकार ने दूरदर्शिता का परिचय दिया है। इससे पहले अप्रैल में भी 25 लाख टन यूरिया आयात के लिए निविदा जारी की गई थी। वैश्विक स्तर पर आपूर्ति बाधित होने और कीमतों में वृद्धि के बावजूद सरकार लगातार अतिरिक्त खरीद और भंडारण की नीति पर काम कर रही है।

हम आपको यह भी बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर केवल आपूर्ति व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा दबाव केंद्र सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर भी पड़ रहा है। खाद विभाग के नवीनतम आकलन के अनुसार यदि मौजूदा वैश्विक कीमतें बनी रहती हैं तो चालू वित्त वर्ष में खाद सब्सिडी का बोझ बढ़कर लगभग 3.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है, जबकि इसके लिए बजट में केवल 1.7 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। युद्ध के बाद यूरिया की वैश्विक कीमतों में 120 प्रतिशत से अधिक, डीएपी में 38 प्रतिशत, सल्फर में 87 प्रतिशत और अमोनिया में 84 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है।

रुपये की कमजोरी के कारण लागत में अतिरिक्त बढ़ोतरी भी हुई है। भारत डीएपी, पोटाश और एनपीके जैसे प्रमुख उर्वरकों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में उथल-पुथल का सीधा असर देश पर पड़ता है।

सामान्य सभा की बैठक में विभागीय कार्यों, बजट उपयोग और विकास योजनाओं की हुई विस्तृत समीक्षा

दंतेवाड़ा। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नंदलाल मुड़ामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं, बजट उपयोग, विकास कार्यों की प्रगति तथा आगामी कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जयंत नाहटा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, जल संसाधन, वन, लोक निर्माण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विभाग से वर्ष 2025-26 में प्राप्त बजट, स्वीकृत कार्यों, व्यय की स्थिति एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग के अंतर्गत नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व विद्यालय भवनों की स्थिति, जर्जर एवं भवन विहीन स्कूलों, आवश्यक मरम्मत कार्यों तथा विद्यार्थियों को समय पर पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। वन विभाग से वर्ष 2025-26 में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य तथा पूर्व वर्षों के बोनस वितरण की स्थिति की जानकारी ली गई। वहीं आर्सेलर मित्तल कंपनी लिमिटेड द्वारा सीएसआर मद से संचालित गतिविधियों एवं विकास कार्यों की समीक्षा भी बैठक में की गई।

जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नंदलाल मुड़ामी ने कहा कि सीएसआर निधि का उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं और पंचायतों की प्राथमिकताओं के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि कंपनियां केवल स्वयं एजेंसी बनकर कार्य करने के बजाय पंचायतों के माध्यम से भी विकास कार्यों को क्रियान्वित करें, जिससे स्थानीय सहभागिता बढ़े और योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री जयंत नाहटा ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने सभी विभागों को स्वीकृत कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग, बजट का प्रभावी उपयोग तथा लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय समन्वय और सतत समीक्षा से विकास कार्यों में गति आएगी तथा जिले के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी। बैठक के दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री अरविंद कुंजाम सहित जिला पंचायत के सदस्यगण एवं विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

फिर विवादों में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी

परीक्षा पोर्टल लीक होने से पेपर लीक की संभावना

बिलासपुर। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में आ गया है। विश्वविद्यालय का समर्थ पोर्टल कथित रूप से हैक होने की जानकारी सामने आने के बाद परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के डाटा की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

आशंका जताई जा रही है कि पोर्टल हैक होने के कारण प्रश्नपत्र भी लीक हो सकते हैं। विश्वविद्यालय में वर्तमान में यूजी और पीजी समेत विभिन्न विभागों की सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही हैं।

इसी दौरान दावा किया गया कि कुछ छात्रों को परीक्षा से पहले ऐसे प्रश्नपत्र प्राप्त हुए, जिनके कई प्रश्न वास्तविक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते हैं। साथ ही छात्रों के निजी डाटा और प्रशासनिक दस्तावेजों के लीक होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने शुक्रवार रात आपात बैठक बुलाकर स्थिति की समीक्षा की। इसके बाद पूरे मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। समिति में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तकनीकी विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है और सात दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

सूत्रों के अनुसार, विश्वविद्यालय के लगभग 32 विभागों के प्रश्नपत्र और अन्य गोपनीय दस्तावेज प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि अब तक प्रश्नपत्र लीक होने के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि पोर्टल कब और कैसे हैक हुआ।यदि जांच में पेपर लीक और डाटा चोरी की पुष्टि होती है, तो यह प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है।

फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और सभी की निगाहें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं।

अमृत सरोवर योजना में अनियमितता का आरोप

ग्रामीणों ने कहा मशीनों से हुआ काम, नहीं हुआ अब तक भुगतान

बस्तर। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग अब बदलाव के दौर में है।लेकिन इस बदलते बस्तर में कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आईं हैं जिसने प्रशासनिक कमी को उजागर किया है।ऐसी ही एक मामला अमृत सरोवर योजना से जुड़ा हुआ है। इस योजना में अब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं।ग्रामीणों का आरोप है कि गांवों में आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए शुरु की गई इस योजना में स्थानीय स्तर काफी हेराफेरी की गई है।जिसे लेकर अब ग्रामीण लामबंद हो रहे हैं।

बस्तर के गांवों में रोजगार और जमीन में वाटर लेवल को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरु की गई अमृत सरोवर योजना में स्थानीय लोगों के बजाय मशीन से काम करवाने का आरोप लगाया गया है। जिसके कारण स्थानीय लोग रोजगार से वंचित रह गए। इतना ही नहीं जिन मजदूरों ने इसमें काम किया, उन्हें वर्षों बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं मिला है। अब ग्रामीण सरकारी दफ्तरों का दरवाजा खटखटा रहे हैं और अपनी मजदूरी मांग रहे हैं।यह पूरा मामला बकावंड ब्लॉक के ग्राम पंचायत सतोसा क्रमांक 2 का है। जहां सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की मिली भगत से भ्रष्टाचार को अंजाम देकर मजदूरी की राशि डकार ली गई है। फिलहाल स्ह्ररूने जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। पीड़ित ग्रामीण सोन सिंह ने बताया कि साल 2022 में अमृत सरोवर तालाब का निर्माण करवाया गया। जिसमें 10 लोगों का समूह बनाकर काम किया गया। तालाब के शुरुआती समय में फोटो खिंचाने के लिए आम लोगों से कुछ दिन काम करवाया गया। इसके बाद करीब 4 महीने तक जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर लगाकर काम करवाया गया। यह काम सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक के कहने पर किया गया। ग्रामीणों ने मिलकर डेढ़ लाख रुपए डीजल के लिए जेसीबी मशीन मालिक को दिया गया। और खुद का ट्रैक्टर लगवाकर काम किया गया। करीब 4 महीने तक उधारी मांगकर ट्रेक्टरों में डीजल डलवाया गया और काम किया गया। लेकिन उसके बाद काम के पैसे के लिए बार-बार सचिव सरपंच और सहायक सचिव को बोला गया। लेकिन दोनों गोल मोल जवाब देते नजर आए और अपना चेहरा छिपाने लगे- सोन सिंह, ग्रामीण

सोन सिंह के मुताबिक कई महीनों के काम और खुद की गाड़ी और पैसा लगाने के बाद केवल 7 हजार रुपए का ही भुगतान हुआ है। कई परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। मजदूरी भुगतान नहीं मिलने के कारण उन्हें कर्ज लेकर परिवार का पालन-पोषण करना पड़ रहा है। अब ग्रामीणों ने मजबूरी में स्ह्ररू बकावंड को भुगतान के लिए गुहार लगाई गई। आपको बता दें कि अमृत सरोवर निर्माण कार्य में जेसीबी और अन्य भारी मशीनों का खुलेआम उपयोग किया गया। जबकि योजना के तहत मजदूरों को प्राथमिकता देकर रोजगार देना था। ग्रामीणों को हर साल रोजगार मिले इसी उद्देश्य से मनरेगा योजना की शुरुआत हुई थी। लेकिन जिम्मेदार केवल ऐसे कार्यों में मशीनों से काम करवाकर न केवल बेरोजगारी को बढ़ावा देते हैं। बल्कि पलायन जैसे समस्या भी पैदा करते हैं। और अन्य मजदूरों की राशि डकार कर भारी भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं।अब देखना होगा कि निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए लंबित मजदूरी भुगतान जल्द जारी करने में प्रशासन कितना सफल होती है।

कलेक्टर ने अफसरों को दिलाई स्वच्छता की शपथ

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। शनिवार से वीकएंड शुरू हो जाता है, लोग हॉली डे के मूड में आ जाते हैं। सरकारी दफ्तारों में काम करने वाले लोग या तो शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, या फिर आस-पास के जिलों में घूमने। एमसीबी जिला अपने आप में टूरिस्ट प्लेस है, तो कई लोग यहां के पर्यटक स्थलों पर आउटिंग के लिए चले जाते हैं। लेकिन इस बार वीकएंड पर एमसीबी जिले में अलग ही नजारा देखने को सामने आया। यहां के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल अमृतधारा जलप्रपात परिसर में भरी गंदगी को प्रशासनिक अफसरों और कर्मचारियों ने मिलकर साफ किया। श्रमदान की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही हैं। कई लोगों ने तो पहली बार देखा

कि जिला प्रशासन के जुड़े अफसर और कर्मचारी किसी पर्यटक स्थल की साफ सफाई में जुटे हैं।

साफ सफाई के लिए पहुंचे अफसर हाथों में फावड़ा और सफाई से जुड़े सामान लेकर पहुंचे थे। कोई कचरा जमा करा था तो कोई कचरे को सुरक्षित तरीके से डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग में भर रहा था। खुद कलेक्टर संतन देवी जांगड़े हाथों में फावड़ा लेकर सफाई अभियान को लीड करती नजर आईं। अमृतधारा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि जिले की पहचान और गौरव का प्रतीक है। इसे स्वच्छ, सुंदर और विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। प्रशासन केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्य कर परिणाम भी दिखाना चाहता है। अमृतधारा के समग्र विकास के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है- संतन देवी जांगड़े, कलेक्टर हाल ही में पीएम मोदी ने सभी लोगों से अपील की है कि वो जरूरत के मुताबिक अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करें। पीएम ने कहा कि अगर हम कार पूलिंग करते हैं तो इससे ईंधन की बचत होती है।

दुकानदार की नजर हटते ही ग्राहक बनी चोर

कोरिया। पुलिस अगर आधे घंटे के भीतर चोरी की वारदात को सुलझा ले, तो आप जरूर कहेंगे कि भाई ये कैसा संभव हुआ।

अक्सर पुलिस पर ये आरोप लगता है कि वो अपराध घटित होने के घंटो बाद मौके - ए - वारदात पर पहुंचती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बैकुंठपुर पुलिस ने ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी की वारदात को महज आधे घंटे में साल्व कर दिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी के जेवरात भी बरामद कर लिए गए। घटना बैकुंठपुर के सराफा बाजार की है। यहां ज्वेलरी खरीदने के बहाने दो शातिर महिलाएं ज्वेलरी शॉप में पहुंचती हैं। दुकानदार उनको जेवरात दिखाने लगता है, इसी बीच दोनों महिलाओं ने दुकानदार की नजरों से बचते हुए कई कीमती जेवरात चोरी कर लिए। चोरी के बाद दोनों महिलाएं वहां से फरार हो गईं। दुकानदार ने जब काउंटर से जेवरात समेटने शुरू किए तो उसे कुछ जेवरात कम नजर आए। उसने तत्काल पूरे स्टॉक को चेक किया। तब उसे पता चला कि करीब 62 हजार के जेवरात नहीं हैं। दुकानदार को यकीन हो गया कि दोनों महिलाओं ने ही उसके जेवरात चोरी किए हैं। दुकानदार ने बिना देर किए पुलिस को इस बात की सूचना दी। हमेशा देर से पहुंचने वाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। उसने दुकान में लगे सीसीटीवी को खंगाला और फिर साइबर सेल की मदद से तत्काल दोनों महिलाओं की तलाश शुरू की। पुलिस को यकीन था कि महिलाएं ज्यादा दूर यहां से नहीं गई होंगी। रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया। पुलिस ने महिलाओं की पहचान के लिए मुखबिरों की भी मदद ली। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई और दोनों महिलाओं को पुलिस ने पहले हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेकर उनकी तलाशी ली गई, तलाशी के दौरान दोनों महिलाओं के पास से चोरी के जेवरात बरामद हुए।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

3 करोड़ का 600 किलो गांजा महासमुंद से पकड़ा गया

महासमुंद। नशे के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी नशे के तस्कर चोरी छिपे तस्करी की वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। इसी कड़ी में आज थाना सिंघोड़ा इलाके के मुरमुरी चौक से नशे की एक बड़ी खेप को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने ट्रक से 600 किलो गांजा पकड़ा है। पकड़े गए गांजे की कीमत 3 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने गांजे के साथ ट्रक को भी जब्त कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के मोबाइल फोन को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस ने बताया कि उसे मुखबिर के जरिए ये खबर मिली थी कि ओडिशा से एक ट्रक गांजा लेकर निकली है, जो महासमुंद जिले से होते हुए निकलेगी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद एंटी नारकोटिक्स टीम के साथ मुरमुरी चौक पर सघन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान वहां पर महाराष्ट्र नंबर की एक संदिग्ध लाल रंग की टाटा माजदा वाहन आकर रुकी। पुलिस की टीम ने बिना देर किए वाहन को चेक करना शुरू किया।

ट्रेन के बाथरूम में फॉल्स सीलिंग के अंदर मिला गांजा

रायगढ़। जीआरपी ने रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर खड़ी हीराकुंड एक्सप्रेस के एसी कोच में छापा मारकर करीब 10 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है, जिसे बाथरूम में फॉल्स सीलिंग के अंदर छिपाकर रखा गया था। पुलिस की भनक लगते ही अज्ञात तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार, रायगढ़ जीआरपी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उड़ीसा की तरफ से आ रही ट्रेन संख्या 20807 अप हीराकुंड एक्सप्रेस में भारी मात्रा में गांजे की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलते ही जीआरपी की टीम अलर्ट हो गई और ट्रेन के रायगढ़ स्टेशन पहुंचते ही घेराबंदी की गई। जीआरपी के जवानों ने जब ट्रेन के एसी कोच की सघन तलाशी ली, तो तस्करों की चालाकी देखकर वे भी दंग रह गए। तस्करों ने गांजे के पैकेटों को बोगी के बाथरूम के ऊपर बनी फॉल्स सीलिंग के भीतर छिपाकर रखा था। पुलिस ने सीलिंग को खोलकर 10 किलोग्राम गांजा सुरक्षित बाहर निकाला और उसे जब्त कर लिया।

पिता ने जहां की नौकरी, वहीं से बेटे ने पार किए 70 लाख के जेवर

धमतरी। धमतरी जिले में सराफा व्यापारी से करीब 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी के पिता लंबे समय तक व्यापारी की दुकान में काम करते रहे थे, जिसके चलते उसने पुराने भरोसे का फायदा उठाकर विश्वास जीता। इसके बाद वह कथित तौर पर लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक, सराफा कारोबारी जसराज जैन को करीब 70 लाख रुपए की चपत लगाने वाला आरोपी हेमंत सोनी पीडब्ल्यूडी विभाग में कर्मचारी है। आरोपी के पिता वर्षों तक जसराज जैन की दुकान में ईमानदारी से नौकरी की थी, जिससे उनके बीच भरोसा मजबूत हो गया था। इसी कारण हेमंत का दुकान में आने-जाने लगा रहा। बाद में कारोबारी लाखों रुपए के कीमती जेवरात भी छोड़कर चले जाता था। लगभग दो महीना पहले युवक करीब 70 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवरात लेकर रफूचक्कर हो गया व्यापारी ने जब उसे फोन किया तो उसका मोबाइल नंबर बंद मिला।

कब्रों से बाहर बिखरी मिलीं इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां

दुर्ग। दुर्ग शहर से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां श्मशान घाट के भीतर इंसानी खोपड़ी, हड्डियां और कंकाल खुले में बाहर बिखरे पाए गए हैं। इतना ही नहीं पास में ही एक प्लास्टिक की थैली में बंधा हुआ मानव कंकाल भी बरामद किया गया। लोग इस बात को लेकर दहशत में हैं कि आखिर पूरी सावधानी के साथ दफनाए गए शवों को कब्र से बाहर कौन निकाल रहा है? यह पूरा मामला रायपुर नाका शमशान घाट का है। श्मशान घाट में इंसानी अवशेष बिखरे होने की जानकारी स्थानीय पार्षद और नागरिकों ने तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही स्मृति नगर चौकी पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (स्नस्रु) की एक्सपर्ट टीम मौके पर पहुंची। स्नस्रु की टीम ने गहन फॉरेंसिक जांच करते हुए तीन अलग-अलग कब्रों से बाहर निकले शरीर के अवशेषों को सैंपल के रूप में कलेक्ट किया है, ताकि उनकी वैज्ञानिक जांच की जा सके। चौकी प्रभारी राजेश साहू ने किसी असामाजिक तत्वों या जानवरों द्वारा छेड़खानी की आशंका जताई है।

प्रशासन पर जनसमस्याओं का निराकरण नहीं करने का आरोप

बिलासपुर। बिल्हा के ग्राम गोढ़ी में आयोजित विकासखंड स्तरीय सुशासन तिहार शिविर के दौरान कांग्रेस नेताओं और ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रशासन पर जनसमस्याओं का निराकरण नहीं करने का आरोप लगाते हुए शिविर का बहिष्कार किया। प्रदर्शन के दौरान राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर दिए गए आवेदनों का अब तक निराकरण नहीं किया गया है। उन्होंने बिजली, पानी, सड़क, खाद-बीज जैसी मूलभूत सुविधाओं की बदहाल स्थिति को लेकर प्रशासन को घेरा। साथ ही पीएचई, कृषि, विद्युत और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से जवाब मांगा। कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला ने नगपुरा-झाल और मोहदा मार्ग के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर भी नाराजगी जताई। उनका आरोप था कि जब उन्होंने मंच से जनसमस्याएं उठानी शुरू की तो उनका माइक बंद कर दिया गया। इसे उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा।

छुईखदान अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के बाद नहीं मिला मुक्तांजलि वाहन

- **मुक्तांजलि वाहन सेवा पर सवाल, ष्टस्ह्र बोले-उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी थी, समय के अभाव और सुविधा को देखते हुए निजी वाहन से निकले परिजन**

खैरागढ़ छुईखदान गंडई। जिले के छुईखदान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आई एक तस्वीर ने स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ ही मानवीय संवेदनाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं। पोस्टमॉर्टम के बाद शव को मुक्तांजलि वाहन भी नसीब नहीं हुआ।

परिजन मालवाहक गाड़ी में शव ले जाने को मजबूर हुए। ग्राम भुरसूली निवासी जेलेब गोड (50 वर्ष) की छत से गिरने के

कारण मौत हो गई। परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिवार को उम्मीद थी कि शासन की मुक्तांजलि सेवा के तहत शव वाहन उपलब्ध होगा और वे अपने प्रियजन को सम्मानपूर्वक घर ले जा सकेंगे।

लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिजनों के अनुसार घंटों इंतजार के बावजूद अस्पताल प्रबंधन शव वाहन की व्यवस्था नहीं कर सका। आखिरकार दुख और बेबसी के बीच परिवार को एक मालवाहक वाहन का इंतजाम करना पड़ा और उसी में शव रखकर गांव ले जाना पड़ा। अस्पताल परिसर से निकली यह तस्वीर केवल एक शव की नहीं, बल्कि व्यवस्था की संवेदनहीनता की तस्वीर बन गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह सिलसिला कब रुकेगा?

जिले में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले झूरानदी दोहरे हत्याकांड में मृत भाई-बहन के शवों को कबाड़ वाहन से गांव ले जाना पड़ा था। वहीं मोगरा के एक मासूम बच्चे की ट्रेन में मौत होने के बाद परिजन राजनांदगांव से बस में शव लेकर खैरागढ़ पहुंचे थे।

हर घटना के बाद सवाल उठे, चर्चा हुई, लेकिन जिम्मेदार विभाग की कार्यप्रणाली में कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया। सरकार ने मुक्तांजलि सेवा इसलिए शुरू की थी ताकि किसी भी परिवार को अंतिम यात्रा के समय आर्थिक या व्यवस्थागत परेशानी का सामना न करना पड़े।

लेकिन जब बार-बार शव वाहन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो यह सवाल उठना लाजिमी है कि यह सेवा कागजों में चल रही है या वास्तव में लोगों तक पहुंच रही है? अस्पताल में मौजूद लोगों ने भी प्रबंधन पर सवाल उठाए और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ष्टरू्वह्र डॉ। आशीष शर्मा ने इस मामले में कहा कि पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शव को परिजनों के गृह ग्राम तक पहुंचाने के लिए मुक्तांजलि वाहन खैरागढ़ से भेजा जा रहा था।

हालांकि वाहन के पहुंचने से पहले ही परिजनों ने समय के अभाव और अपनी सुविधा को देखते हुए निजी वाहन से शव को गांव ले जाने का निर्णय लिया।

बिलासपुर के व्यापार विहार में लगी आग

आसमान में धुएं का गुबार, तेल का गोदाम होने से काबू पाने में लगी कड़ी मशक्कत

बिलासपुर। शहर के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र व्यापार विहार में शनिवार सुबह एक खाद्य तेल (एडिबल ऑयल) के गोदाम में भीषण आग लग गई। यह पूरा मामला तारबाहर थाना क्षेत्र का है, जहां तेल की मौजूदगी के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यह हादसा बिलासपुर के व्यापार विहार स्थित मोहन ब्रदर्स (चौधरी एजेंसी) के गोदाम में सुबह करीब 9 बजे हुआ। इस गोदाम में भारी मात्रा में खाद्य तेल का स्टॉक रखा हुआ था। अचानक गोदाम के भीतर से आग की ऊंची और तेज लपटें उठने लगीं। गोदाम में तेल होने के कारण आग देखते ही देखते पूरे परिसर में फैल गई। आसमान में काले धुएं का एक बड़ा गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगा। इसे देखकर आसपास के दुकानदार, कर्मचारी और खरीदारी करने आए ग्राहक भी अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग (फायर ब्रिगेड) को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और तारबाहर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तेल की आग होने के कारण इस पर काबू पाने में काफी दिक्कतें आईं, लेकिन टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग को पूरी तरह शांत किया।

संक्षिप्त समाचार

पद्मविभूषण तीजन बाई के स्वास्थ्य को लेकर प्रदेश सरकार सजग

रायपुर। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को देश-दुनिया में प्रतिष्ठित करने वाली सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका एवं पद्मविभूषण से सम्मानित श्रीमती तीजन बाई के अस्वस्थ होने की सूचना पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने तत्काल पहल की। उन्होंने अपने सहयोगी को एम्स रायपुर भेजकर पद्मविभूषण श्रीमती तीजन बाई के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मंत्री श्री अग्रवाल ने दूरभाष पर तीजन बाई के परिजनों से चर्चा कर उनका हालचाल जाना और भरोसा दिलाया कि राज्य शासन उनकी चिकित्सा एवं आवश्यक सहायता के लिए पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ खड़ा है। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि उपचार संबंधी हर संभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि तीजन बाई केवल लोक कलाकार नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना और लोक परंपराओं की जीवंत प्रतीक हैं। उन्होंने अपनी अद्भुत गायन शैली, प्रभावशाली प्रस्तुति और लोककला के प्रति समर्पण से पंडवानी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई है। उनके योगदान ने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

गोदावरी पावर एंड इस्पात के मैनेजर के यहां चोरों ने बोला धावा

रायपुर। टाटीबंध स्थित पार्थिवी पेसिफिक के डाफोडिल ब्लॉक में रहने वाले स्वप्नेश्वर हरिचंदन के घर अज्ञात चोरों ने धावा बोला 5.55 लाख रुपए के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड सिलतरा में मैनेजर का काम करते हुए उनकी पत्नी और बच्चे के साथ गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए ओडिशा स्थित गांव गए हुए थे। हरिचंदन सुबह घर में ताला लगाकर गए हुए थे कि यह घटना घटित हो गई। हरिचंदन की रिपोर्ट पर आमानाका पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उसकी तलाश में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरिचंदन की पत्नी बच्चे की गर्मी की छुट्टी लगने के कारण ओडिशा स्थित अपने घर गई हुई थी। हरिचंदन रोजाना की तरह सुबह घर में ताला लगाकर गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड सिलतरा ड्यूटी पर गए थे। दोपहर करीब 3 बजे लौटने पर घर का मुख्य दरवाजा टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो बेडरूम में रखी गोदरेज अलमारी और लॉकर भी टूटा हुआ मिला। इसके बाद हरिचंदन ने आमानाका पुलिस को इसकी सूचना दी और सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरु की।

रायपुर जिला कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान भाई ने किया भाई पर हमला

रायपुर। रायपुर जिला कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान कोर्ट परिसर स्थित पुलिस चौकी के सामने भाई ने भाई पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दोनों भाई जिला कोर्ट में नियमित पेशी पर रायपुर जिला कोर्ट पहुंचे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरु हो गया और देखते ही देखते मारपीट भी मारपीट शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। घटना कोर्ट परिसर और पुलिस चौकी के ठीक सामने हुई, जिससे वहां मौजूद वकीलों, पुलिस कर्मियों और लोगों में अफरा-तफरी मच गई। हमले के बाद घायल युवक को तत्काल अंबेढकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस हमले के पीछे पुरानी रंजिश और पारिवारिक विवाद के एंगल से जांच कर रही है।

धनुहार नाला पर अमरपुर एनीकट योजना के निर्माण हेतु 4.26 करोड़ रूपये स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा कोरिया जिले के विकासखंड बैकुंठपुर धनुहार नाला पर अमरपुर एनीकट के निर्माण कार्य के लिए 4 करोड़ 26 लाख 40 हजार रूपये स्वीकृत किये गये हैं। योजना के निर्माण से भू-जल संवर्धन, निस्तारी, पेयजल एवं आवागमन के साथ ही कृषकों द्वारा स्वयं के साधन से 120 हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। योजना के निर्माण कार्य कराने के लिए मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कहार जल संसाधन विभाग अम्बिकापुर को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

पावर कंपनी से ईडी मनीष गुप्ता सहित आठ कर्मियों को भावभीनी विदाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी से कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) मनीष कुमार गुप्ता सहित कुल 8 अधिकारी-कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। पॉवर कंपनीज़ के मुख्यालय सेवा भवन में आयोजित समारोह में प्रबंध निदेशक (जनरेशन) श्री एस. के. कटियार, प्रबंध निदेशक (ट्रांसमिशन) श्री राजेश कुमार शुक्ला तथा प्रबंध निदेशक (डिस्ट्रीब्यूशन) श्री भीम सिंह कंवर ने सेवानिवृत्त ईडी श्री गुप्ता को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। प्रबंध निदेशकगणों ने कहा कि श्री गुप्ता के समर्पण, उत्कृष्ट कार्यशैली एवं अनुभवों से पॉवर कंपनी के विकास कार्यों को नई दिशा और गति मिली हैं। सेवानिवृत ईडी श्री गुप्ता ने अपने सेवाकाल के अनुभव साझा करते हुए अपने सेवायात्रा में मिले सहयोग के लिए प्रबंधन, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

राज्यपाल डेका ने जनकल्याणकारी योजनाओं पर दिया विशेष जोर

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने शनिवार को लोकभवन में वीडियों कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की बैठक लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, जल संरक्षण, पौधा रोपण एवं पर्यावरण संवर्धन, जैविक खेती, टी.बी उन्मूलन, सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति, विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि विकास कार्यों के बेहतर परिणाम के लिए अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण करना चाहिए और योजनाओं की जमीनी स्थिति की जानकारी रखनी चाहिए। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित करने पर बल दिया।

राज्यपाल ने गोद ग्राम बिजली में जल संरक्षण को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कहा कि जनभागीदारी के माध्यम से सभी शासकीय भवनों तथा प्रधानमंत्री आवासों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित किया जाए। इसके लिए विस्तृत रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जिले में पुराने डबरियों, चेक डैमों एवं अन्य जल स्रोतों के संरक्षण और मरम्मत को प्राथमिकता देने को कहा। साथ ही बड़े किसानों को खेतों में डबरी निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने तथा छोटे एवं मध्यम किसानों को भी जल संरक्षण गतिविधियों से जोडने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने रेत के अवैध उत्खनन पर प्रभावी रोक लगाने तथा वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित खनन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे नदियों की प्राकृतिक स्थिति में सुधार होगा और भूजल स्तर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। राज्यपाल ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले के सभी शासकीय कार्यालयों, अस्पतालों, संस्थानों एवं रिहायशी क्षेत्रों में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए।

बैठक में जैविक एवं प्राकृतिक खेती की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने किसानों को प्राकृतिक खेती और हाइड्रोपोनिक्स खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने प्राकृतिक खेती से उत्पादित वस्तुओं में वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और लोगों को रसायनमुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे। उन्होंने धान के साथ-साथ उद्यानिकी एवं रबी फसलों को भी प्रोत्साहन देने पर बल दिया। राज्यपाल ने जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों की जानकारी लेते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार पर बल दिया। उन्होंने मुक्तिधामों को सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त करने तथा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नवाचारों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। वेस्ट मटेरियल के बेहतर उपयोग के लिए नवीन मॉडल विकसित करने पर भी जोर दिया।

राज्यपाल ने जिले में कार्यरत लखपति दीदियों की गतिविधियों की जानकारी ली और उत्कृष्ट कार्य करने वाली दीदीयों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मल्टीपल डिजीज से पीड़ित लोगों का समुचित उपचार सुनिश्चित किया जाए। विशेष पिछड़ी जनजातियों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी उन्होंने दिए। राज्यपाल ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने नशे की हालत में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई, रेंडम जांच तथा नशामुक्ति केंद्रों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को समन्वित प्रयास करने होंगे।

राज्यपाल ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के ग्रामों में बिजली, पानी, सड़क तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन समुदायों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाने के निर्देश दिए। बैठक में राज्यपाल ने रेड क्रॉस की सदस्यता अभियान को व्यापक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रेड क्रॉस के माध्यम से रक्तदान शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। बैठक में राज्यपाल की उपसचिव सुश्री निधि साहू एवं श्री रूपेन्द्र कवि, गरियाबंद जिले के कलेक्टर श्री बी. एस उइके, सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

पीएम सूर्य घर योजना बनी बिजली बचत की नई ताकत

■ जशपुर के प्रभाष कुमार जैन को हर माह हजारों रुपये की राहत

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में प्रदेशभर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के माध्यम से हजारों परिवार स्वच्छ ऊर्जा अपनाकर बिजली खर्च में उल्लेखनीय कमी ला रहे हैं। जशपुर जिले के कुनकुरी निवासी एवं व्यवसायी श्री प्रभाष कुमार जैन इसकी सफलता का एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आए हैं।

श्री जैन ने अपने घर की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 5 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित कराया है। इस परियोजना पर लगभग 3.50 लाख रुपये की लागत आई, जिसमें उन्हें शासन की ओर से 78 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई। इससे सोलर सिस्टम लगाने की लागत में उन्हें बड़ी आर्थिक सहायता मिली।

श्री जैन बताते हैं कि पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल 4 से 5 हजार रुपये तक आता था। सोलर पैनल स्थापित होने के बाद बिजली खर्च में लगातार कमी आ रही है और आने वाले समय में इससे और अधिक बचत होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी उन्हें ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुई। आवेदन से लेकर स्थापना तक की पूरी प्रक्रिया सरल और पारदर्शी रही, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। श्री जैन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना आम परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी है। इससे न केवल बिजली बिल का बोझ कम होता है, बल्कि स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलता है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य घरों को सस्ती, स्वच्छ और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में नागरिक इस योजना से जुड़कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को मिली नई गति

जिलों को 2677 करोड़ से अधिक की राशि जारी

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रभावी क्रियान्वयन को नई गति मिली है। राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास निर्माण कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों को 2677.15 करोड़ रुपए की केंद्रीय एवं राज्यांश राशि जारी की गई है। यह राशि एसएनए स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से जिलों को आवंटित की गई है, ताकि पात्र हितग्राहियों के आवास निर्माण कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरे किए जा सकें।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब को पक्का घर का संकल्प छत्तीसगढ़ में तेजी से साकार हो रहा है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रदेश का कोई भी पात्र परिवार पक्के आवास जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित न रहे। पक्का घर केवल चार दीवारें नहीं, बल्कि एक परिवार के सम्मान, सुरक्षा, स्थायित्व और बेहतर भविष्य की मजबूत नींव है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास निर्माण का कार्य तेजी से संचालित किया जा रहा है। राज्य में प्रतिदिन 1600 से अधिक पक्के आवासों का निर्माण किया जा रहा है तथा विगत ढाई वर्षों में 10.60 लाख से अधिक आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही 6 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कर छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि लाखों गरीब परिवारों के सपनों, आत्मसम्मान और सुरक्षित जीवन की कहानी है।

मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जारी राशि का उपयोग प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशा-निर्देशों के अनुरूप करते हुए पात्र हितग्राहियों के आवास शीघ्र पूर्ण कराए जाएं, ताकि प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को समय पर सुरक्षित एवं सम्मानजनक पक्का आवास उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में महिला स्व-सहायता समूहों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। प्रदेश में 10 हजार से अधिक महिला स्व-सहायता समूहों की दीदियां निर्माण सामग्री आपूर्ति कार्य से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं और लखपति दीदी बनने की दिशा में आगे बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि महिला सशक्तीकरण, आजीविका संवर्धन और सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम बन रही है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों को विकास की मुख्यधारा से जोडने के लिए भी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। ऐसे परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराकर उनके जीवन में सुरक्षा, स्थायित्व और विश्वास का नया वातावरण तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नवाचार के तहत 1.5 लाख से अधिक आवासों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित किया गया है, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही हितग्राहियों की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-1290 संचालित की जा रही है तथा योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों में क्यूआर कोड भी प्रदर्शित किए गए हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार सुशासन, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

वंदे मातरम पर सियासत : भूपेश बघेल ने भाजपा को दी चुनौती

कहा- कोई भी कार्यकर्ता बिना देखे गाकर दिखाए

रायपुर। केरलम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को लेकर छिड़े विवाद के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को चैलेंज किया कि वह एक साथ बिना देखे वंदे मातरम् दिखाएं। बघेल ने कहा कि कांग्रेस के हर कार्यक्रमों की शुरुआत वंदे मातरम से होती है, जबकि भाजपा के लोग कभी इसे गाते तक नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के जिला स्तर के कार्यक्रमों में भी वंदे मातरम् गाया जाता है।

पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने अपने दिल्ली दौरे को लेकर जानकारी दी कि शुक्रवार को उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। पंजाब के संबंध में राहुल गांधी और खड़गे से चर्चा हुई। इस दौरान पंजाब में होने वाले आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में संगठनात्मक रणनीति और चुनावी तैयारियों पर विचार-विमर्श किया गया।

केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर भाजपा द्वारा शुरू किए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को जनसंपर्क अभियान जरूर चलाना चाहिए, क्योंकि जनता उनके जवाब का इंतजार कर रही है। जनता भाजपा से सवाल पूछेगी।

सुशासन तिहार : अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचाने सरकार संकल्पित

■ 509 समस्याओं का मौके पर ही हुआ ऑन द स्पॉट निपटारा

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुरूप अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने और जनता की समस्याओं को उनके घर के पास ही सुलझाने का महाअभियान सुशासन तिहार 2026 लगातार सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। इसी कड़ी में धमतरी जिले के विकासखंड नगरी के ग्राम पंचायत घठुला में आयोजित क्लस्टर स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जहां प्रशासनिक मुस्तैदी के चलते एक ही छत के नीचे 509 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर ग्रामीणों को बड़ी राहत दी गई।

इस शिविर में घठुला, लटियारा, पाईकभाठा, रतावा, पोड़ागांव, लखनपुरी, फरसगांव, पांवद्वार, गिधावा, बोरई, घुटकेल, मैनपुर, बिरनासिली एवं लिखमा सहित कुल 14 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। शिविर में न केवल लोगों की शिकायतें सुनी गईं, बल्कि विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की लाइव जानकारियां भी साझा की गईं, जिससे लोगों को जागरूक होने का अवसर मिला।

शिविर के दौरान कुल 528 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 523 आवेदन विभिन्न मांगों से संबंधित और 05 आवेदन जनता की शिकायतों से जुड़े थे। शासन और प्रशासन की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्राप्त आवेदनों में से 509 का मौके पर ही निपटारा कर हितग्राहियों को तत्काल राहत प्रदान की गई, जबकि शेष बचे आवेदनों के लिए उपस्थित आला अधिकारियों ने संबंधित विभागों को समय-सीमा के भीतर त्वरित कार्रवाई करने के कड़े निर्देश जारी किए।

जनदर्शन में मंत्री राजेश अग्रवाल ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने जनदर्शन कार्यक्रम के तहत सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड के ग्राम हरिहरपुर पहुंचकर ग्रामीणों से आत्मीय भेंट-मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं, आवश्यकताओं और विकास संबंधी मांगों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। लोगों ने सड़क, पेयजल, बिजली, राजस्व, स्वास्थ्य एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को मंत्री श्री अग्रवाल के समक्ष रखा। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि शासन की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है।

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि जनता से सीधा संवाद और जनभावनाओं से जुड़ाव ही सुशासन का वास्तविक आधार है। क्षेत्रवासियों की अपेक्षाओं, विश्वास और विकास के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों का गंभीरता से परीक्षण कर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

मंत्री श्री अग्रवाल ने ग्रामीणों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी तथा पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार गांव, गरीब, किसान और अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग (भ/स) अम्बिकापुर मण्डल अम्बिकापुर

निविदा आमंत्रण तिथि :- 27.05.2026

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना

01. निविदा की विस्तृत जानकारी के लिये Log in करें http://eproc.cgstate.gov.in
02. संबंधित संभाग-स.क्र. 01 से 06 पत्थलगांव एवं स.क्र. 07 से 10 जशपुर संभाग
03. स.क्र. 01 से 10 'द' वर्ग एवं ऊपर ठेकेदार
04. ऑनलाईन निविदा डालने की अंतिम तिथि - 19.06.2026

सरल क्र	एन.आई.टी. क्र	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
1	2	3	4
1	55	लोक निर्माण विभाग उपसंभाग क्र. 02 पत्थलगांव के अंतर्गत शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का विशेष मरम्मत कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	50.00
2	56	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र. 01 पत्थलगांव अंतर्गत शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत का कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	60.00
3	57	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र. 01 पत्थलगांव अंतर्गत शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का रंगाई पोताई का कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	60.00
4	58	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र. 01 पत्थलगांव अंतर्गत शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का विशेष मरम्मत का कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	100.00
5	59	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र. 02 पत्थलगांव अंतर्गत शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत का कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	30.00
6	60	लो.नि.वि. उपसंभाग क्र. 02 पत्थलगांव अंतर्गत शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का रंगाई पोताई का कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	20.00
7	61	लोक निर्माण विभाग उपसंभाग क्रमांक 02 जशपुर के अंतर्गत शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का रंगाई पोताई एवं डिस्टेम्परिंग का कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	25.00
8	62	लोक निर्माण विभाग उपसंभाग कुनकुरी के अंतर्गत शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का रंगाई पोताई एवं डिस्टेम्परिंग का कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	25.00
9	63	लोक निर्माण विभाग उपसंभाग क्रमांक 01 जशपुर के अंतर्गत शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का रंगाई पोताई एवं डिस्टेम्परिंग का कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	75.00
10	64	लोक निर्माण विभाग उपसंभाग कुनकुरी के अंतर्गत शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का विशेष मरम्मत एवं एम ओ डब्ल्यू का कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	35.00

जी-262701074/9

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग, अम्बिकापुर, मण्डल अम्बिकापुर

फ्लेक्सिबल जियोपॉलिटिक्स के कूटनीतिक निहितार्थ

कमलेश पांडे

लचीली भूराजनीति यानी फ्लेक्सिबल जियोपॉलिटिक्स का जन्मदाता भारत की देखा-देखी अब पूरी दुनिया में इसका प्रचलन बढ़ रहा है। इसे मोदी डॉक्ट्रिन कहना ज्यादा उचित होगा, जो गुटनिरपेक्षता का हाइब्रिड पालिसी संस्करण है। आम कहानी वाली भाषा में कहें तो खुल जा सिमसिम और बंद हो जा सिमसिम वाली वैश्विक कूटनीति ही अब लचीली भूराजनीतिक बन चुकी है। दरअसल, फ्लेक्सिबल जियोपॉलिटिक्स यानी लचीली भूराजनीति का अर्थ ऐसी अवसरवादी विदेश नीति से है, जिसमें देश अपने हित के अनुसार कभी दोस्ती का दरवाज़ा खोलते हैं और कभी तुरंत बंद कर लेते हैं। आज की दुनिया में यही फ्लेक्सिबल जियोपॉलिटिक्स तेजी से बढ़ रही है। जिसके सफल उपयोगकर्ता टीम पीएम मोदी हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ भारत जैसे उन देशों को होता है जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली हों, तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर हों, सैन्य रूप से सक्षम हों, और बहुध्रुवीय दुनिया में संतुलन साधना जानते हों। यही वजह है कि भारत इसे अपनाकर दुनिया के शीर्षस्थ देशों की कतार में शामिल होने की दिशा में बढ़ता जा रहा है। सवाल है कि आखिर इससे किसका भला होगा? तो इसके कई जवाब होंगे, जिनमें पहला है महाशक्तियों का सबसे अधिक लाभ : संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और आंशिक रूप से रूस-भारत जैसी शक्तियाँ इस नीति से सबसे अधिक फायदा उठाती हैं। पूर्वक सवाल है क्यों? तो सीधा सा जवाब है कि वे परिस्थितियों के अनुसार गठबंधन बदल सकती हैं। आर्थिक प्रतिबंधों, सैन्य दबाव और तकनीकी नियंत्रण का इस्तेमाल कर सकती हैं। मित्र और प्रतिद्वंद्वी दोनों से व्यापार जारी रख सकती हैं। उदाहरण- अमेरिका, चीन से प्रतिस्पर्धा भी करता है और व्यापार भी। चीन रूस का साझेदार है लेकिन पश्चिमी बाजार भी नहीं छोड़ना चाहता। वहीं, रूस पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद एशियाई देशों से संबंध मजबूत कर रहा है। दूसरा, मध्यम शक्तियों का भी फायदा: भारत, तुर्किये, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जैसे देश मल्टी-अलाइनमेंट नीति से लाभ उठा रहे हैं। भारत इसका बड़ा उदाहरण है, जो क्वाड में भी है, ब्रिक्स में भी, रूस से रक्षा सहयोग भी रखता है, और अमेरिका से तकनीकी साझेदारी भी बढ़ाता है। इससे रणनीतिक स्वतंत्रता बनी रहती है, निवेश कई दिशाओं से आता है, और वैश्विक मंचों पर प्रभाव बढ़ता है। तीसरा, कॉर्पोरेट और टेक कंपनियों को बड़ा लाभ: एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट जैसी वैश्विक कंपनियाँ देशों की प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाती हैं। क्योंकि देश उन्हें निवेश आकर्षित करने के लिए टैक्स छूट देते हैं, सप्लाई चेन अपने यहाँ लाने की कोशिश करते हैं, और टेक्नोलॉजी कंपनियों को रणनीतिक साझेदार मानते हैं। सवाल है कि ऐसी मतलबी कूटनीति से नुकसान किसका? तो जवाब होगा कि- पहला, छोटे और कमजोर देशों का: अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और छोटे एशियाई देशों पर दबाव बढ़ता है कि वे किसी एक खेमे का समर्थन करें। वे कर्ज जाल, प्रतिबंध, राजनीतिक दबाव, और सामरिक प्रतिस्पर्धा के बीच फँस जाते हैं। दूसरा, वैश्विक स्थिरता का: ऐसी कूटनीति में भरोसा कम होता है। देश स्थायी मित्र नहीं बल्कि तात्कालिक हित देखते हैं। इससे युद्धों की आशंका बढ़ती है, व्यापारिक तनाव बढ़ता है, और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ कमजोर पड़ती हैं। वहीं, भारत के लिए यह दौर अवसर भी है और चुनौती भी। यदि भारत नवाचार, निर्माण, रक्षा आत्मनिर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा, और तकनीकी क्षमता को मजबूत करता है, तो वह इस बदलती दुनिया में संतुलनकारी शक्ति बन सकता है। लेकिन यदि आर्थिक और तकनीकी शक्ति पर्याप्त न हो, तो ऐसी खुल जा सिमसिम कूटनीति में बड़े देश छोटे देशों को केवल रणनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।

दिल्ली में क्वॉड का मंथन आगाज़

किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर नई दिल्ली में 26 मई 2026 को संपन्न हुई, क्वॉड विदेश मंत्रियों की बैठक केवल एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं थी,बल्कि तेजी से बदलते वैश्विक शक्ति-संतुलन के बीच चार प्रमुख लोकतांत्रिक शक्तियों, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का रणनीतिक मंथन थी। ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में युद्ध और तनाव ने पूरी दुनियाँ की ऊर्जा सुरक्षा,समुद्री व्यापार और सप्लाई चेन को अस्थिर कर दिया है,वहीं हिंद- प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता, समुद्री विस्तारवाद और भू- राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने वैश्विक शक्तियों की चिंताओं को और गहरा कर दिया है। इसी पृष्ठभूमि में दिल्ली में बैठे चार यार केवल बयान देने नहीं, बल्कि भविष्य की विश्व-व्यवस्था के नए समीकरण तय करने के लिए एक मंच पर दिखाई दिए। भारतीय विदेश मंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक और संयुक्त प्रेस वार्ता ने स्पष्ट संकेत दिया कि क्वॉड अब केवल एक संवाद मंच नहीं,बल्कि वैश्विक रणनीतिक स्थिरता, समुद्री सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बचाने वाला प्रभावशाली समूह बन चुका है। मैं यह मानता हूं कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, अमेरिकी सैन्य गतिविधियों, ऊर्जा संकट की आशंकाओं और इंडो- पैसिफिक में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच दिल्ली में हुआ यह मंथन आने वाले समय की वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने वाला बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।

साथियों भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो,ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी की उपस्थिति ने यह स्पष्ट कर दिया कि क्वॉड देशों के बीच रणनीतिक समन्वय अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका है। यह बैठक ऐसे समय हुई जब पूरी दुनियाँ पश्चिम एशिया की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ईरान से जुड़े घटनाक्रम, अमेरिकी सैन्य सक्रियता और ऊर्जा आपूर्ति मार्गों पर बढ़ते खतरे ने वैश्विक आर्थिक अस्थिरता की आशंकाओं को बढ़ा दिया है।ऐसे में नई दिल्ली की यह बैठक केवल इंडो-पैसिफिक तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें वैश्विक भू - राजनीतिक चुनौतियों और आर्थिक

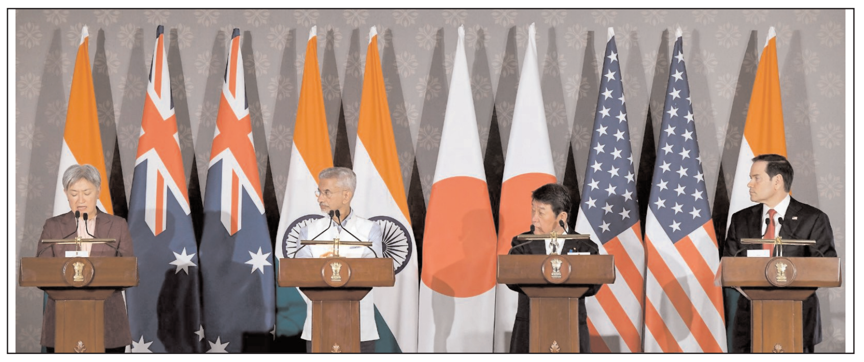

सुरक्षा के व्यापक पहलुओं पर भी विचार हुआ।भारतीय विदेश मंत्री ने अपने उद्घाटन वक्तव्य में स्पष्ट कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र वैश्विक विकास और स्थिरता का मुख्य इंजन बन चुका है। उन्होंने इस क्षेत्र में स्वतंत्र,खुले और समावेशी वातावरण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का दबाव,आक्रामकता या एकतरफा शक्ति-प्रदर्शन क्षेत्रीय संतुलन के लिए खतरा है।उन्होंने भरोसेमंद और पारदर्शी साझेदारी को वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। उनका यह बयान अप्रत्यक्ष रूप से चीन की आक्रामक नीतियों और विस्तारवादी रणनीति की ओर संकेत माना गया। भारत ने साफ संदेश दिया कि वह इंडो-पैसिफिक में किसी भी प्रकार की अस्थिरता को स्वीकार नहीं करेगा और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।क्वॉड बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू समुद्री सुरक्षा और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पर हुआ व्यापक विचार- विमर्श रहा। हिंद-प्रशांत क्षेत्र विश्व व्यापार का सबसे बड़ा समुद्री मार्ग है, जहां से वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक बढ़ती सैन्य गतिविधियों और सामरिक प्रतिस्पर्धा ने इन समुद्री मार्गों की सुरक्षा को अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बना दिया है। बैठक में इस बात पर सहमति बनी किअंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी देश को एकतरफा तरीके से समुद्री नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति न मिले। यह संदेश स्पष्ट रूप से चीन की समुद्री गतिविधियों और उसके बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में सटीकता से देखा जा रहा है।

साथियों,बैठक में वैश्विकसप्लाई चेन की मजबूती पर भी विशेष जोर दिया गया। कोविड महामारी और उसके बाद रूस-यूक्रेन युद्ध तथा पश्चिम एशिया संकट ने यह साबित कर दिया कि दुनियाँ किसी एक देश या क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता का जोखिम नहीं उठा सकती। क्वॉड देशों ने महत्वपूर्णखनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ सप्लाई चेन को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर और रक्षा उपकरणों के निर्माण में इन खनिजों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी तक इन क्षेत्रों में चीन का दबदबा माना जाता रहा है,लेकिन क्वॉड देशों की नई रणनीति का उद्देश्य वैकल्पिक आपूर्ति तंत्र विकसित करना है ताकि सटीकता से किसी एक देश पर निर्भरता कम हो सके।

साथियों, भारत और अमेरिका के बीच क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन को लेकर हुए समझौते को इस बैठक की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यह समझौता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत तेजी से उभरती हुई विनिर्माण शक्ति बनना चाहता है और इसके लिए उसे सुरक्षित तथा विश्वसनीय संसाधन आपूर्ति की आवश्यकता है। वहीं अमेरिका चीन पर निर्भरता कम करने की वैश्विक रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच यह सहयोग भविष्य में तकनीकी और औद्योगिक साझेदारी को नई ऊंचाई दे सकता है।उभरती हुई प्रौद्योगिकियों और साइबर सुरक्षा पर भी बैठक में व्यापक चर्चा हुई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, साइबर डिफेंस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आज वैश्विक शक्ति संतुलन के नए उपकरण बन चुके हैं। क्वॉड देशों ने इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और सुरक्षित तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर सहमति जताई। विशेष रूप से साइबर अपराध और डिजिटल जासूसी को लेकर साझा चिंता व्यक्त की गई। डिजिटल दुनिया में बढ़ते खतरों को देखते हुए यह सहयोग भविष्य में सामरिक सटिका से महत्व का आधार बन सकता है।

साथियों,आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराना भी इस बैठक का महत्वपूर्ण संदेश रहा। क्वॉड देशों ने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकार का आतंकवाद मानवता और वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है। भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है और इस बार भी उसने आतंकवाद के खिलाफ कठोर वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। यह संदेश केवल क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि उन शक्तियों को भी संकेत था जो अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को समर्थन देती हैं।मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया के हालात पर हुई चर्चा ने इस बैठक को और अधिक वैश्विक महत्व प्रदान किया। ईरान से जुड़े तनाव, अमेरिकी सैन्य हमलों और क्षेत्रीय संघर्षों ने वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार मार्गों को प्रभावित करने की आशंका पैदा कर दी है। क्वॉड देशों ने चिंता जताई कि यदि यह संकट और गहराया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ऊर्जा कीमतों में वृद्धि, सप्लाई चेन में बाधा और आर्थिक अस्थिरता पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि दिल्ली बैठक में पश्चिम एशिया के मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया गया।

साथियों, बैठक में यह भी स्पष्ट हुआ कि क्वॉड अब केवल सुरक्षा सहयोग तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक साझेदारी के व्यापक ढांचे में विकसित हो रहा है। यह समूह एक ऐसे वैकल्पिक वैश्विक सहयोग मॉडल के रूप में उभर रहा है जो लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता और नियम-आधारित व्यवस्था पर आधारित है। क्वॉड की बढ़ती सक्रियता इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन बहुध्रुवीय स्वरूप की ओर बढ़ सकता है।हालांकि इस बार नेताओं का पूर्ण शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हो सका, लेकिन विदेश मंत्रियों की बैठक ने यह साबित कर दिया कि क्वॉड की गति धीमी नहीं हुई है। भारत ने औपचारिक रूप से क्वॉड की अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया को सौंप दी। यह हस्तांतरण केवल प्रक्रियात्मक नहीं, बल्कि सहयोग की निरंतरता का प्रतीक भी है।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

अग्नि को प्रकट करने के लिये श्ररणी जांडी की दो लड़कियों को मन्थन करते हुये व्यास जी के हृदय में चिन्ता उत्पन्न हुई कि।।23।। (इन दोनों काष्ठों के परस्पर संघर्ष से) अग्नि की तरह मेरे कैसे पुत्र उत्पन्न होगा : क्योंकि पुत्र को उत्पन्न करने वाली अरणी रूप स्त्री मेरे घर में नहीं है।। 25।।

ऋषि इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश मार्ग से जाती हुई परम सुन्दरी घृताची नाम वाली अप्सरा दीख पड़ी।।26-30।। वे व्रतधारी व्यास जी उसे देखकर तत्काल ही कामाक्रांत हो गये।। 31

(ख) घृताची ऋषि के भय से शुकी रूप बनाकर वहाँ से गुजर गई।।3।। तब व्यास जी का शुक्र सहसा मन्थना-रणी में ही गिर गया ॥ 7॥ जिससे व्यास जी के समान मनोहर रूप वाले शुकदेव जी प्रादुर्भूत हुये।।8।।

समाधान

उक्त कथा में भी व्यास जी के अमोघवीर्य की ही महिमा लक्षित होती है। जब कि तप के प्रभाव से रजोवीर्य के त्रिना भी मानसी सन्तान का उत्पन्न हो जाना नेदादि शास्त्रों में लिखा है, तब स्थूल शरीर की कारण सामग्री से परिपूरित अमोध वीर्य के द्वारा पुत्र का उत्पन्न हो जाना किसी प्रकार भी असम्भव नहीं कहा जा सकता। भानसी किंवा तापसी सृष्टि का वर्णन वेदों में डंके की चोट किया है, यथा-

(क) मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्।

(अथर्व 16 । 52 । 1)

(ख) श्रद्धाया दुहिता तपसोऽधिजाला स्वसा ऋषीणां भूतकृतां बभूव ।

(अधर्व 6 । 133 ।4)

अर्थात् (क) सृष्टि के आरम्भ में मनसो रेतः ही था। (ख) श्रद्धा की पुत्री तप से उत्पन्न हुई थी, सूत्रधार ऋषियों को बहिन लगती थी।

क्रमशः ...

लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर

हर्षवर्धन पान्डे

भारत अपनी गौरवशाली संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के लिए दुनिया में जाना जाता है। यहाँ अनेक ऐसे योद्धा, शासक, शासिकाओं और वीरांगनाओं ने जन्म लिया है जिनका नाम लोककल्याण जैसे अनेक कार्यों में आज भी गर्व के साथ लिया जाता है। इनमें से अहिल्याबाई होल्कर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देश में जब भी किसी महिला का जीवन आदर्श, वीरता, त्याग, राष्ट्रभक्ति के लिए सदा याद किया जाता है, उनमें रानी अहिल्याबाई होल्कर अग्रणी हैं। वे 18वीं शताब्दी की एक ऐसी प्रेरणादायक महिला थी जिनका पूरा जीवन आज समाज के लिए बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। होल्कर राजवंश का इतिहास जितना समृद्ध रहा है, उतनी ही अहिल्याबाई होल्कर की विरासत लोककल्याण के कार्यों के लिए जानी जाती है।

अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई, 1725 को अहमदनगर, महाराष्ट्र के गाँव छौंदी में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। एक साधारण से किसान परिवार में जन्मी अहिल्याबाई होलकर छोटी उम्र से ही अपनी संस्कृति पर गर्व करती थी, साथ ही प्रजा में रह रहे आमजनों की पीड़ा की अनुभूति भी करती थी। इनके पिता मनकोजी राव शिन्दे शिवभक्त थे।

कुशल प्रशासन एवं कर्तव्यपरायणता जैसे अपने अनेक मानवीय गुणों के कारण अहिल्याबाई होल्कर के द्वारा कराये गए अनेक कार्य देश में आज भी बड़े गर्व और आदर के साथ याद किये जाते हैं। उन्होंने अपने जीवनकाल में कभी कहीं कोई समझौता नहीं किया। पूरी कर्तव्यनिष्ठा व अनुशासन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए लोककल्याण एवं सामाजिक सरोकारों के प्रति संकल्पबद्ध होकर हर पल का सदुपयोग ही किया शायद यही वजह थी कि समाज के बीच उनकी एक अलग ही विशिष्ट पहचान और प्रतिष्ठा थी। भारतीय संस्कृति एवं लोककल्याण के कार्यों के प्रति उन उनका सम्मान का भाव उनके द्वारा किए गए अनेकानेक कार्यों में देखा जा सकता था। हमारी संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन हेतु जन -जन को प्रेरित व प्रोत्साहित करना उनका स्वाभाविक गुण था। सचमुच उनका जीवन आज समाज के लिए प्रेरणा व प्रोत्साहन का अविरल स्रोत है। ऐसी महान धर्म प्रेमी, संस्कृति प्रेमी व मानवता प्रेमी कर्मयोगी शासिका के जीवन से आज हर किसी को प्रेरणा लेने की जरूरत है।

अहिल्याबाई एक विनम्र एवं उदार वीरांगना थी जिनके अंदर गरीबों और असहाय व्यक्ति के लिए दया और परोपकार की भावना भरी हुई थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। मल्हारराव के निधन के बाद उन्होंने पेशवाओं की गद्दी से आग्रह किया कि उन्हें क्षेत्र की प्रशासनिक बागडोर सौंपी जाए। मंजूरी मिलने के बाद 1766 में रानी अहिल्यादेवी मालवा की शासक बन गईं। उन्होंने तुकोजी होल्कर को सैन्य कमांडर बनाया। उन्हें उनकी राजसी सेना का पूरा सहयोग मिला। अहिल्याबाई ने कई युद्ध का कुशल नेतृत्व भी किया। वे एक साहसी योद्धा के साथ ही एक कुशल तीरंदाज भी थी जो हाथी की पीठ पर चढ़कर लड़ती थी।

अब्राहम अकॉर्ड्स : बदलती वैश्विक राजनीति का दर्पण

किशन सनमुखदास भावनानीं

वैश्विक स्तरपर पश्चिम एशिया की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है,जहां कूटनीति, धर्म, सुरक्षा, ऊर्जा और वैश्विक शक्ति संतुलन एक-दूसरे से टकराते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के केंद्र में है अब्राहम अकॉर्ड्स एक ऐसा समझौता जिसे अमेरिका ने इजरायल और अरब देशों के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी खत्म करने के लिए तैयार कराया। अमेरिका और इजरायल इसे शांति, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हैं, जबकि ईरान और उसके समर्थक इसे मुस्लिम दुनिया को विभाजित करने और फिलिस्तीनी मुद्दे को कमजोर करने की रणनीति मानते हैं। यही कारण है कि आज डोनाल्ड ट्रम्प और ईरान के नए सुप्रीम लीडर मौजतबा खामनेई के बीच वैचारिक और रणनीतिक टकराव खुलकर सामने आ रहा है। एक ओर ट्रम्प मुस्लिम देशों को इजरायल के साथ जोड़कर एक नए पश्चिम एशियाई सुरक्षा गठबंधन का निर्माण करना चाहते हैं, तो दूसरी ओर मौजतबा खामनेई अमेरिका और इजरायल के खिलाफ इस्लामी एकजुटता का आह्वान कर रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि इस पूरे संघर्ष के पीछे केवल धर्म या विचारधारा नहीं, बल्कि तेल, व्यापार मार्ग, सैन्य प्रभाव, हथियारों का बाजार, चीन- रूस की बढ़ती मौजूदगी और वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई भी छिपी हुई है। इसलिए अब्राहम अकॉर्ड्स केवल एक शांति समझौता नहीं, बल्कि 21वीं सदी की नई जियोपॉलिटिकल व्यवस्था का प्रतीक बन चुका है।

साथियों, बात अगर हम अब्राहम अकॉर्ड्स को समझने की करें तो, यह वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में शुरू हुई द्विपक्षीय समझौतों की एक श्रृंखला है,जिसका उद्देश्य इजरायल और अरब देशों के बीच राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाना था। 15 सितंबर 2020 को वाशिंगटन में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजरायल के साथ औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर

किए। इसके बाद दिसंबर 2020 में मोरक्को इस प्रक्रिया में शामिल हुआ और सूडान ने भी सामान्यीकरण पर सहमति व्यक्त की, हालांकि वहां की राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रक्रिया धीमी पड़ गई। बाद में नवंबर 2025 में कजाकिस्तान ने भी औपचारिक रूप से इस समूह में शामिल होने की घोषणा की। यह पूरी प्रक्रिया इसलिए ऐतिहासिक मानी गई क्योंकि 1994 में जॉर्डन और 1979 में मिस्र के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अरब देशों ने इजरायल के साथ खुले संबंध स्थापित किए। अब्राहम नाम यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों अब्राहमिक धर्मों की साझा सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों को ध्यान में रखकर चुना गया, ताकि इसे धार्मिक टकराव के बजाय साझा विरासत के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

साथियों, अमेरिका और इजरायल को इस समझौते की आवश्यकता कई कारणों से महसूस हुई। सबसे बड़ा कारण था ईरान का बढ़ता प्रभाव। पिछले दो दशकों में ईरान ने इराक, सीरिया, लेबनान, यमन और गाजा तक अपने प्रभाव का विस्तार किया। हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे संगठनों के जरिए तेहरान पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजरायल की रणनीतिक चुनौतियां बढ़ा रहा था। अमेरिका समझता था कि यदि अरब देशों और इजरायल को एक साझा सुरक्षा ढांचे में नहीं जोड़ा गया, तो ईरान धीरे-धीरे पूरे क्षेत्र में प्रभावशाली शक्ति बन सकता है। इसलिए अब्राहम अकॉर्ड्स को एक प्रकार के एंटी-ईरान सुरक्षा गठबंधन के रूप में भी देखा गया। इजरायल के लिए यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे उसे अरब दुनिया में वैधता मिली और उसकी क्षेत्रीय अलग-थलग स्थिति कमजोर हुई। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए यह समझौता पश्चिम एशिया में अपनी पकड़ बनाए रखने का साधन था, खासकर उस समय जब चीन और रूस धीरे-धीरे इस क्षेत्र में अपनी आर्थिक और सामरिक उपस्थिति बढ़ा रहे थे।

साथियों, ईरान का विरोध केवल वैचारिक नहीं बल्कि सामरिक भी है। तेहरान को डर है कि यदि सऊदी अरब जैसे बड़े मुस्लिम देश भी इस समझौते में शामिल हो गए, तो पश्चिम एशिया में एक ऐसा संयुक्त मोर्चा बन जाएगा जिसमें अमेरिका, इजरायल और खाड़ी देश एक साथ खड़े होंगे। इससे ईरान की रणनीतिक घेराबंदी हो सकती है। यही कारण है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मौजतबा खामनेई लगातार मुस्लिम देशों से अमेरिका और इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने हाल के भाषणों में दावा किया कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकाने अब सुरक्षित नहीं हैं और अमेरिका का प्रभाव कमजोर पड़ रहा है। यह बयान केवल राजनीतिक संदेश नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का संकेत भी है। ईरान यह दिखाना चाहता है कि वह अभी भी क्षेत्रीय प्रतिरोध धुरी का सबसे बड़ा केंद्र है।दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रम्प अब्राहम अकॉर्ड्स को अपनी सबसे बड़ी विदेश नीति उपलब्धियों में गिनते हैं। ट्रम्प प्रशासन की रणनीति यह रही कि अरब देशों और इजरायल के बीच संबंध सामान्य कराकर अमेरिका एक नया पश्चिम एशियाई ब्लॉक तैयार करे, जो ईरान और चीन दोनों के प्रभाव को सीमित कर सके। ट्रम्प चाहते थे कि सऊदी अरब, पाकिस्तान, कतर और तुर्की जैसे प्रभावशाली मुस्लिम देश भी इस समझौते में शामिल हों। लेकिन यहां उन्हें कठिन विरोध का सामना करना पड़ा। सऊदी अरब ने साफ कहा कि फिलिस्तीन के लिए एक अपरिवर्तनीय और विश्वसनीय रास्ते के बिना वह इजरायल के साथ पूर्ण संबंध सामान्य नहीं करेगा।

साथियों 27 मई 2026 को पाकिस्तान ने भी वैचारिक आधार पर इससे इनकार कर दिया। पाकिस्तान के नेताओं ने कहा कि उनका देश फिलिस्तीनी मुद्दे से समझौता नहीं कर सकता। तुर्की और ईरान ने भी इसे मुस्लिम दुनियाँ को बांटने की अमेरिकी रणनीति बताया। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि क्या जो देश अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल नहीं होंगे, वे अमेरिकी प्रतिबंधों का शिकार बन सकते हैं? प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कहना कठिन है, क्योंकि अमेरिका ने किसी देश को केवल समझौते से बाहर रहने के कारण प्रतिबंधित नहीं किया है। लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका अपनी विदेश नीति में आर्थिक और सामरिक दबाव का इस्तेमाल करता रहा है। ईरान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिस पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। पाकिस्तान पर भी समय- समय पर अमेरिकी दबाव दिखाई देता रहा है। हालांकि सऊदी अरब जैसे बड़े ऊर्जा उत्पादक देशों पर सीधे प्रतिबंध लगाना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे वैश्विक तेल बाजार और अमेरिकी हित दोनों प्रभावित हो सकते हैं। फिर भी यह संभावना बनी रहती है कि जो देश अमेरिकी रणनीतिक ढांचे से बाहर रहेंगे, उन्हें रक्षा सहयोग, निवेश या कूटनीतिक समर्थन के मामलों में नुकसान सटीकता से झेलना पड़ सकता है।

साथियों, अब्राहम अकॉर्ड्स के समर्थकों का मानना है कि यह समझौता पश्चिम एशिया को युद्ध और कट्टरता से निकालकर आर्थिक सहयोग और विकास की ओर ले जा सकता है। उनका तर्क है कि यदि अरब और इजरायल आर्थिक रूप से एक-दूसरे पर निर्भर होंगे, तो संघर्ष की संभावना कम होगी। आज पश्चिम एशिया दो बड़े वैचारिक और रणनीतिक ध्रुवों में बंटता दिखाई दे रहा है। एक ध्रुव अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगी अरब देशों का है, जो सुरक्षा, तकनीक और आर्थिक साझेदारी के जरिए नया क्षेत्रीय ढांचा तैयार करना चाहते हैं। दूसरा ध्रुव ईरान और उसके समर्थक समूहों का है, जो इसे अमेरिकी वर्चस्व और इजरायली विस्तारवाद के खिलाफ प्रतिरोध की लड़ाई मानते हैं। इस संघर्ष में चीन और रूस भी धीरे-धीरे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

आज का इतिहास

1868 पहली लोकप्रिय साइकिल दौड़ पेरिस डे सेंट-क्लाउड में आयोजित की गयी।

1878 जर्मनी के युद्धपोत एसएमएस ग्रोसर करफर्स्ट के डूबने से 284 लोगों की मौत।

1907 अमेरिका के न्यूयार्क शहर में पहली बार टैक्सी सेवा शुरू की गयी।

1916 जर्मन कैसरलीश मरीन और ब्रिटिश रॉयल नेवी प्रथम विश्व युद्ध की सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाई जूटलैंड की गहन लड़ाई में भिड़ गए।

1921 अमेरिका के तुलसा, ओक्लाहोमा में एक बड़े पैमाने पर दौड़ दंगा शुरू हुआ, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे धनी अफ्रीकी-अमेरिकी समुदाय, गिनीवुड जिला आग से नष्ट हो गया था।

1924 सोवियत संघ ने बीजिंग सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, बाहरी मंगोलिया को चीन गणराज्य का अभिन्न अंग के रूप में संदर्भित किया, जिसका संप्रभुता सोवियत संघ ने सम्मान करने का वादा किया।

1935 पाकिस्तान के क्वेटा शहर में भीषण भूकंप से 50 हजार से अधिक लोगों की मौत।

1941 यूनाइटेड किंगडम ने इराक के अपने कब्जे को पूरा कर लिया, अब्द अल-इलाह को फैसल II के लिए रीजेंट के रूप में सत्ता में वापस कर दिया।

1961 दक्षिण अफ्रीका संघ दक्षिण अफ्रीका गणराज्य बन गया। यह चार अलग ब्रिटिश उपनिवेशों के एकीकरण के साथ अस्तित्व में आया, केप कॉलोनी, नेटाल कॉलोनी, ट्रांसवाल कॉलोनी और ऑरेंज रिवर कॉलोनी।

1981 पुलिस और सरकार द्वारा प्रायोजित भीड़-भाड़ वाली एक संगठित भीड़ ने श्रीलंका के जाफना में सार्वजनिक पुस्तकालय को जलाना शुरू कर दिया, जो 20 वीं शताब्दी के बेथलॉनिकलस्म के सबसे हिंसक उदाहरणों में से 97,000 से अधिक वस्तुओं को नष्ट कर दिया।

1986 1986 फीफा विश्व कप मेक्सिको में शुरू हुआ

1994 दक्षिण अफ्रीका गुट निरपेक्ष आन्दोलन का 109वाँ सदस्य राष्ट्र बना।

1996 बेंजामिन नेतान्याहू इजरायल के प्रधानमंत्री बने।

1999 कृष्ण प्रसाद भट्टराई ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ये नेपाल के पहले संसद के पहले सभामुख तथा बहुदलीय व्यवस्था की पुनर्स्थापना के बाद नेपाल के पहले प्रधानमन्त्री थे।

कांग्रेस ने कर्नाटक का मुख्यमंत्री बदलकर धर्मसंकट टाला!

कमलेश पांडे

कर्नाटक में कांग्रेस इस समय एक गहरे राजनीतिक धर्मसंकट में दिखाई दे रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री बदलकर उसने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। जिस तरह से आलाकमान के निर्देश पर सिद्धारमैया की जगह डी के शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है, वह दूरदर्शिता का परिचायक है। लेकिन सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री बदलने से समस्या का स्थायी हल निकल चुका है? या फिर कोई और नई समस्या पनपेगी! कांग्रेस का अतीत इसी बात की चुगली करता है।

चूंकि कांग्रेस के लिए जहां एक ओर सत्ता संतुलन मायने रखता है, तो वहीं दूसरी ओर एक स्थिर और टिकाऊ सरकार की चुनौती उसके समक्ष मौजूद है, जो चुनावी मुद्दा भी 2028 के विधानसभा चुनाव में बनेगा। और इसी बीच मुख्यमंत्री बदलने की लगातार चल रही चर्चाओं को सही साबित करके और अपना नया मुख्यमंत्री घोषित करके उसने कर्नाटक के राजनीतिक तापमान बढ़ा चुकी है।

सवाल यह है कि क्या नेतृत्व परिवर्तन वास्तव में समाधान बन सकता है, या फिर यह कांग्रेस के लिए कोई नया संकट खड़ा कर देगा?

इसलिए आइए पहले कर्नाटक कांग्रेस के मौजूदा समीकरण को समझते हैं। वह यह कि वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्य में जनाधार और प्रशासनिक अनुभव वाले नेता माने जाते हैं, जबकि उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार संगठन, संसाधन और रणनीतिक राजनीति के मजबूत स्तंभ हैं। चूँकि गत 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में दोनों की बड़ी भूमिका रही थी। इसलिए सत्ता संतुलन शुरू से ही संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। उम्मीद है कि अब डी के शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री बदलना केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन का प्रश्न बन चुका था, जो अब जाकर पूरा हुआ।

ऐसे में सुलगता सवाल है कि आखिर दोनों नेताओं के बीच का संतुलन कैसे बदला और क्या मुख्यमंत्री बदलने से इसका हल निकल सकता है? तो जवाब होगा कि सैद्धांतिक रूप से नेतृत्व परिवर्तन से असंतोष कम किया जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक राजनीति में ऐसा प्रयोग हमेशा सफल नहीं होता। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि बदलाव सहमति से हुई या दबाव में, सत्ता हस्तांतरण सम्मानजनक हुआ या टकरावपूर्ण, संगठन और विधायकों का समर्थन किसके

साथ रहे और जनता इसे स्थिरता माने या आंतरिक संघर्ष। क्योंकि यदि बदलाव समझौते की तरह दिखाई दिया है, तो कांग्रेस इसे संतुलन की राजनीति कह सकती है। लेकिन विपक्ष इस लंबी चली खींचतान को अस्थिरता के रूप में ही पेश करेगा। आइए पहले समझते हैं कि कांग्रेस का तल्ख अतीत क्या कहता है?

पहला, राजस्थान मॉडल: बदलाव टला, लेकिन संघर्ष बढ़ा। आपने गौर किया होगा कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय तक नेतृत्व संघर्ष चला। फिर भी कांग्रेस हाईकमान स्पष्ट निर्णय लेने से बचता रहा। नतीजा यह निकला कि सरकार लगातार अंदरूनी तनाव में रही और युवा बनाम वरिष्ठ नेतृत्व की बहस तेज हुई। इससे चुनावी नैरेटिव कमजोर हुआ और अंततः सूबाई सत्ता भाजपा के हाथों गंवानी पड़ी। यह उदाहरण बताता है कि निर्णय टालना भी कभी-कभी संकट को लंबा कर देता है और विनाशकारी प्रभाव छोड़ता है।

दूसरा, मध्यप्रदेश मॉडल: असंतोष की कीमत सत्ता गंवाकर चुकाई। आपने महसूस किया होगा कि मध्यप्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बढ़ते असंतोष को समय रहते नहीं संभाला गया। आखिरकार सिंधिया समर्थक विधायकों के जाने से कांग्रेस सरकार गिर गई। यह कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सबक बना कि केवल हाईकमान नियंत्रण हर बार पर्याप्त नहीं होता।

तीसरा, पंजाब मॉडल: नेतृत्व परिवर्तन उल्टा भी पड़ सकता है। आपने समझा होगा कि पंजाब में कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। उद्देश्य था एंटी-इन्कम्बेंसी कम करना और सामाजिक समीकरण मजबूत करना। लेकिन पार्टी के भीतर विभाजन और बढ़ गया। इससे संगठनात्मक भ्रम पैदा हुआ और चुनाव में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। इससे यह संदेश गया कि देर से किया गया नेतृत्व परिवर्तन हमेशा लाभकारी नहीं होता।

तो ऐसी उलझाऊ परिस्थितियों में आखिर कांग्रेस का असली धर्मसंकट क्या है?

देखा जाए तो कांग्रेस के सामने फिलवक्त तीन बड़ी चुनौतियाँ हैं- एक, स्थिरता बनाम महत्वाकांक्षा : यदि बदलाव नहीं हुआ तो एक धड़ा असंतुष्ट रह सकता है। यदि बदलाव हुआ तो दूसरा धड़ा अस्थिर हो सकता है। दूसरा, दक्षिण भारत का राजनीतिक महत्व- कर्नाटक फिलहाल दक्षिण भारत में कांग्रेस की सबसे बड़ी सत्ता है। यह राज्य केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय रणनीति का केंद्र बन चुका है। तीसरा, भाजपा को अवसर न मिले: भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस की आंतरिक राजनीति पर नजर रखे हुए है। लिहाजा कांग्रेस जानती है कि सार्वजनिक संघर्ष विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे सकता है।

कांग्रेस संभवतः विभिन्न रास्तों पर विचार कर रही होगी- पहला, समयबद्ध सत्ता परिवर्तन और फिर संगठन और सरकार के बीच नई जिम्मेदारियों का बंटवारा। मुख्यमंत्री बदलने के बाद उसकी सबसे संभावित रणनीति फिलहाल यही दिखती है कि पार्टी किसी भी बदलाव को संघर्ष नहीं बल्कि सहमति के रूप में प्रस्तुत करना चाहेगी।

वास्तव में अतीत कांग्रेस को यह सिखाता है कि नेतृत्व परिवर्तन न करना भी जोखिम है और गलत समय पर करना उससे बड़ा जोखिम। इसलिए कर्नाटक में पार्टी इसी संतुलन को साधने की कोशिश कर चुकी है, क्योंकि यहां गलती केवल राज्य सरकार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक संदेश को भी प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन यानी मुख्यमंत्री बदलने का निर्णय बेहद सावधानी पूर्वक किया गया है, क्योंकि पार्टी को यह एहसास है कि सत्ता परिवर्तन की आंतरिक राजनीति कई राज्यों में उसे भारी नुकसान पहुँचा चुकी है। यही कारण है कि पार्टी राजस्थान और मध्यप्रदेश जैसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति से बचना चाहती दिख रही थी और उसने डी के शिवकुमार के धैर्य और प्रयासों को ग्रेस दिया।

क्वाड की प्रासंगिकता की अटकलों पर विराम

शोभना जैन

निरंतर गहराते अंतरराष्ट्रीय तनाव और बड़ी ताकतों के बीच बनते-बिगड़ते रिश्तों के इस दौर में राजधानी में इसी सप्ताह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह 'क्वाड' के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। भारत की मेजबानी में हुए इस आयोजन से पिछले कुछ समय से क्वाड के भविष्य और प्रासंगिकता को लेकर चल रही अटकलों और सवालों को कुछ विराम तो लग ही गया। यह क्वाड बैठक ऐसे समय हुई जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र की भू-राजनीतिक स्थिति लगातार बदल रही है। ऐसे में बैठक में सदस्य देशों के बीच साझा क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने की कोशिश काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि चारों सदस्य समुद्री लोकतंत्र हैं जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र के अलग-अलग छोर पर हैं। लेकिन दूरी के बावजूद इन सभी के बीच समुद्री क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ा है, जिसमें निगरानी और डोमेन जागरूकता, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के अंदर से केबल, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ ही वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत बनाने और पश्चिम एशिया व यूक्रेन की स्थिति जैसे क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। क्वाड की हाल की इस बैठक के बाद विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि वे ऐसे स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि करते हैं जो देशों को अपनी राह खुद तय करने की क्षमता और लचीलापन विकसित करने में सक्षम बनाता है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य से वे सहयोग को और बढ़ाने तथा क्षेत्र को ठोस लाभ पहुंचाने वाली मजबूत पहलों को आगे बढ़ाने पर सहमत हैं। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते वैश्विक व्यापार के निर्बाध

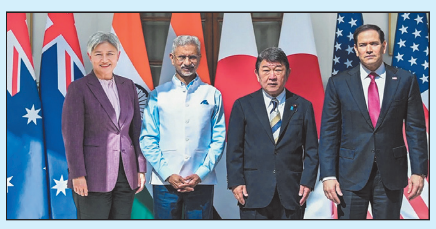

प्रवाह का आह्वान किया, क्षेत्र में वाणिज्यिक पोतों पर ईरान द्वारा शुल्क लगाए जाने की आलोचना की और पूर्वी चीन सागर एवं दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई। क्वाड के सदस्य देशों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य सक्रियता की पृष्ठभूमि में समुद्री निगरानी और बंदरगाह अवसंरचना को मजबूत करने के लिए नए उपायों की घोषणा की तथा महत्वपूर्ण खनिजों एवं ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार किया। लेकिन चीन को यह घटनाक्रम क्षुब्ध करने के लिए काफी था। क्वाड देशों के समुद्री निगरानी पहल शुरू करने पर प्रतिक्रिया देते हुए उसने कहा कि चीन अपने खिलाफ विशिष्ट 'छोटे समूहों' का विरोध करता है। उसने यह भी कहा कि क्वाड को लेकर चीन का रुख स्पष्ट है। चीन शुरू से ही क्वाड को अपने खिलाफ बना एक सैन्य समूह बताता है। क्वाड का गठन 2017 में हुआ था और 2019 में विदेश मंत्री स्तर का रूप लेने के बाद इसने शिखर बैठक का रूप लिया था। लेकिन 2022 के बाद से इन देशों के नेता इस मंच से नहीं मिले। इन तमाम स्थितियों के चलते क्वाड की प्रासंगिकता को ले कर सवाल उठने लगे। ऐसे में नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्री स्तरीय बैठक, चारों समुद्री ताकतों के बीच हुए विचार-विमर्श और साझेदारी व सहयोग के रास्ते पर चलने की प्रतिबद्धता को क्वाड को गति देने का एक संकेत माना जा रहा है।

भारत और साइप्रस के बीच हुई रणनीतिक साझेदारी के मायने

कमलेश पांडे

भारत और साइप्रस के बीच हाल में हुई रणनीतिक साझेदारी और विभिन्न समझौतों के कई बड़े कूटनीतिक, सामरिक और आर्थिक मायने हैं। देखा जाए तो यह केवल द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार नहीं, बल्कि यूरोप, भूमध्यसागर, पश्चिम एशिया और वैश्विक शक्ति-संतुलन से भी जुड़ा कदम माना जा रहा है। चूंकि तुर्की और साइप्रस के बीच गहरी दुश्मनी है, इसलिए भारत उसे तुर्किये के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि तुर्किये भारत के चिर शत्रु पाकिस्तान का मित्र है। इस प्रकार भारत के रणनीतिकारों ने एक तीर से कई शिकार किये हैं।

उल्लेखनीय है कि साइप्रस एक द्वीप है, इसलिए उसकी लैंड बॉर्डर तुर्की के साथ नहीं लगती है। लेकिन समुद्री मार्ग से साइप्रस और तुर्की के बीच की दूरी महज 65 से 70 किलोमीटर है। यही नहीं, साइप्रस तुर्की से 85 गुना छोटा देश है। इसलिए तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है। चूंकि तुर्की तो साइप्रस को एक देश भी नहीं मानता। लिहाजा दोनों देशों के बीच टकराव हमेशा बना रहता है। गत दिनों उसी देश साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्स दिल्ली के दौरे पर आए। इस दौरान भारत और साइप्रस के बीच 14 मुद्दों पर ऐतिहासिक डील फाइनल हो गई।

आइए अब हम आपको इन 14 डील्स के बारे में विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले यह समझिए आखिर में ये प्रमुख डील और समझौते क्या हैं? तो यह जान लीजिए कि भारत और साइप्रस ने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक उन्नत किया है। जिससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग रोडमैप, आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्यसमूह, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, निवेश, शिक्षा, संस्कृति और व्यापार से जुड़े कई समझौते हुए हैं। लिहाजा, इनके कूटनीतिक मायने बेहद अहम हैं-

पहला, यूरोप में भारत की रणनीतिक पकड़ मजबूत हुई है, क्योंकि साइप्रस यूरोपीय संघ (ईयू) का सदस्य है। ऐसे में भारत को यूरोप के भीतर एक भरोसेमंद सहयोगी मिल रहा है। साइप्रस ने भारत-ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को आगे

बढ़ाने का समर्थन भी किया है। इसका अर्थ है कि भारत की यूरोप तक आर्थिक पहुँच मजबूत होगी। इससे भारतीय कंपनियों के लिए यूरोपीय बाज़ार के दरवाजे और खुल सकते हैं। वहीं भारत की कूटनीतिक आवाज़ ईयू मंचों पर अधिक प्रभावी हो सकती है।

दूसरा, तुर्किये-पाकिस्तान समीकरण का संतुलन तोड़ने में अब भारत को मिलेगी सहूलियत, क्योंकि साइप्रस और तुर्किये के बीच लंबे समय से तनाव है। दूसरी ओर तुर्किये कई बार पाकिस्तान के पक्ष में कश्मीर मुद्दे पर बोलता रहा है। ऐसे में भारत-साइप्रस निकटता को एक भू-राजनीतिक संतुलन के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि भारत ने साइप्रस की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन दोहराया, जबकि साइप्रस भारत के आतंकवाद विरोधी रुख के करीब दिखा।

तीसरा, चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब भी माना जा रहा है, क्योंकि भारत, साइप्रस और यूरोप के बीच बढ़ती साझेदारी को चीन की बेल्ट एंड रोड रणनीति के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। विशेषकर समुद्री व्यापार, सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है।

चौथा, आईएमईसी कॉरिडोर को मजबूती मिलेगी, क्योंकि भारत-मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) भारत की बड़ी रणनीतिक परियोजनाओं में से एक है। खास बात यह कि साइप्रस पूर्वी भूमध्यसागर में स्थित होने के कारण इस कॉरिडोर का महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक और समुद्री केंद्र बन सकता है। इससे भारत का यूरोप तक व्यापार तेज हो सकता है, स्वेज नहर पर निर्भरता कुछ हद तक घट सकती है, और चीन समर्थित समुद्री नेटवर्क का विकल्प तैयार हो सकता है।

पांचवां, समुद्री और रक्षा सहयोग बढ़ेगा, क्योंकि दोनों देशों ने रक्षा रोडमैप और समुद्री सुरक्षा सहयोग पर जोर दिया है। इसके मायने हिंद महासागर से लेकर भूमध्यसागर तक भारत की रणनीतिक उपस्थिति बढ़ सकती है। इससे साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी नेटवर्क मजबूत होंगे, जिससे भारतीय नौसैनिक पहुँच को अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है।

छठा, भारत की मल्टी-अलाइनमेंट नीति को मजबूती मिलेगी। चूंकि भारत अब केवल एक ध्रुव पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इसलिए रूस, अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों और भूमध्यसागरीय देशों के साथ समानांतर संबंध बनाकर भारत वैश्विक शक्ति-संतुलन में अपनी स्वतंत्र स्थिति मजबूत कर रहा है। साइप्रस के साथ समझौते इसी नीति का हिस्सा माने जा रहे हैं।

इसके आर्थिक मायने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि निवेश दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, शिपिंग, फिनटेक, पर्यटन और स्टार्टअप सेक्टर में सहयोग बढ़ सकता है। साइप्रस भारतीय निवेश के लिए यूरोप का गेटवे बन सकता है। यह डील भारत के लिए बड़ा संदेश भी है, क्योंकि यह डील दिखाती है कि भारत अब केवल दक्षिण एशिया तक सीमित शक्ति नहीं रहना चाहता, बल्कि यूरोप, भूमध्यसागर, पश्चिम एशिया, और वैश्विक व्यापार मार्गों में भी अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक भूमिका बढ़ा रहा है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत-साइप्रस समझौते केवल छोटे देश के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंध नहीं हैं, बल्कि यूरोप में रणनीतिक प्रवेश, तुर्किये-पाकिस्तान-चीन समीकरण का संतुलन, ढ्रुल्ध्रष्ट कॉरिडोर की मजबूती, और वैश्विक शक्ति राजनीति में भारत की बढ़ती सक्रियता का संकेत हैं।

एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार, लेकिन ...

राधा रमण

सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को वैध ठहराते हुए साफ-साफ कहा कि चुनाव आयोग को इसका अधिकार है। अदालत ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के संवैधानिक लक्ष्य को आगे बढ़ाती है। यह लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया की वैधानिकता को चुनौती देने वाली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) समेत करीब 20 याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद -324 एवं जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 21(3) के तहत एसआईआर कराने का अधिकार है। अदालत ने माना कि एसआईआर की प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया। साथ ही कहा कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची में नाम शामिल करने की पात्रता के लिहाज से नागरिकता की सीमित जांच करने का अधिकार है। हालांकि ऐसी जांच नागरिकता का निर्धारण नहीं मानी जा सकती है।

अदालत के इस फैसले से देश के नागरिकों में सन्नाटा पसरा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनतादल यूनाईटेड (जदयू) खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है, जबकि विपक्ष के दल मौन हैं। याचिकाकर्ता एडीआर के वकील प्रशांतभूषण जरूर इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बता रहे हैं। उधर, बिहार के चुनाव परिणामों से उत्साहित चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, पुडुचेरी, असम, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, लक्ष्यद्वीप और अंडमान निकोबार समेत 13 और राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करा ली है। इनमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी में हाल ही विधानसभा के चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं। बाकी राज्यों में भी एसआईआर के आदेश दिए जा चुके हैं। दिल्ली में भी 20 जून से एसआईआर शुरू किया जाएगा।

दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने एसआईआर को लेकर नहीं बल्कि एसआईआर में जल्दबाजी को लेकर

सवाल उठाया था। उनका कहना था कि चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की घोषणा के बाद आखिरकार जल्दबाजी (महज एक माह) में एसआईआर क्यों करा रहा है। वह भी तब जब आधे से अधिक बिहार की जनता बाढ़ की विभीषिका से जूझ रही है। लोगों के समक्ष जान-माल की चुनौती है और चुनाव आयोग मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण करा रहा है। फिर, एसआईआर में जुड़े लोगों का प्रोपर प्रशिक्षण भी नहीं हो पाया है। याचिकाकर्ताओं ने बिहार में करीब 65 लाख मतदाताओं का नाम कटने की बात कही थी। उधर, एसआईआर के दौरान एक दल विशेष के नेता चुनाव आयोग का प्रवक्ता बने फिर रहे थे। इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे थे।

अदालत का फैसला साक्ष्यों पर आधारित होता है। अदालत ने माना कि यह प्रक्रिया एक असाधारण परिस्थिति में की गई थी, लेकिन इसे अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची संशोधन से जुड़े प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया गया।

उधर, याचिकाकर्ताओं ने 65 लाख मतदाताओं का नाम काटे जाने की बात जरूर कही थी, लेकिन अपनी याचिका के समर्थन में सबूत के तौर पर 65 मतदाताओं का नाम जुटाने में असमर्थ रहे। विपक्ष के राजनीतिक दल भी ट्विटर पर बयानबाजी और दिखावे के प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं कर सके। यदि वह बयानबाजी छोड़ सबूत अदालत के सामने रखते तो शायद अदालत को चुनाव आयोग को क्लीनचिट नहीं देना पड़ता।

सुप्रीम कोर्ट ने भले ही चुनाव आयोग को एसआईआर पर क्लीनचिट दे दी है लेकिन आयोग की निष्पक्षता पर अदालत मौन है। सरकार ने पहले ही संसद से यह तय कर दिया है कि चुनाव आयोग के किसी फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसा आजादी के बाद पहली बार हुआ है। वैसे भी जब से ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सबसे अधिक सवाल उठते रहे हैं।

उधर, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर एक और मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाई बी चंद्रचूड़ ने सरकार को सुझाव दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन में सीजेआई को भी शामिल करना चाहिए। उनका तर्क था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। फिलहाल, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और नेता प्रतिपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन में शामिल होते हैं और बहुमत का फैसला माना जाता है। जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना था कि सरकार का मंत्री प्रधानमंत्री की राय से इतर कैसे सोच सकता है। इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई को शामिल होना चाहिए। हालांकि सरकार ने उसे नहीं माना है। पिछले दिनों वर्त्तमान सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान इस पर कड़ी टिप्पणी की थी। मामला अभी अदालत के विचाराधीन है। देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट उस मामले में क्या फैसला देता है।

इस बीच जाने-माने समाजसेवी और याचिकाकर्ताओं में से एक योगेन्द्र यादव ने एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि मेरे अनुसार, इस मामले की दिशा पिछले वर्ष अगस्त में ही तय हो गई थी, जब एसआईआर के खिलाफ तीन दिन दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उसकी संवैधानिक वैधता की जांच से ध्यान हटाकर खुद को एक उपभोक्ता फोरम में बदल लिया था। जहां संवैधानिक सिद्धांतों की जगह शिकायत निवारण और प्रशासनिक मध्यस्थता पर जोर था। यादव ने कहा कि उन्हें अदालत के इस फैसले से कोई आश्चर्य नहीं है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। बड़ा सवाल यह कि क्या आज के नेताओं में लोकलाज बचा है!

छीन ली मुख्यमंत्री की कुर्सी : कैसे यहां तक पहुंचे शिवकुमार?

राकेश कुमार

कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनने जा रहे कांग्रेस के संकटमोचक डीके शिवकुमार के लिए सत्ता पाना कभी आसान नहीं रहा। वैसे तो, 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते समय ही तय कर लिया गया था कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ढाई-ढाई साल मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन नवंबर 2025 में जब समयसीमा करीब आई तो सिद्धारमैया इससे मुकर गए।

आखिरकार, छह माह तक चली सियासी खींचतान के बाद शिवकुमार अपनी महत्वाकांक्षा को परवान चढ़ाने में सफल रहे। यह पहला मौका नहीं हैं, जब उन्होंने अपना हक पाने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ राजनीतिक दांवपेचों का सहारा लिया हो। वह एक बार खुद कह चुके हैं, सत्ता मिलती नहीं है, इसे छीनना पड़ता है। दरअसल, 1999 में जब एसएम कृष्णा मुख्यमंत्री पद संभालने जा रहे थे तो उनके साथ मिलकर मंत्रियों की सूची शिवकुमार ने ही तैयार कराई थी। इसे आलाकमान को भेजा गया और जब अंतिम सूची आई तो शिवकुमार का नाम उसमें नहीं था। उन्होंने जरा भी देर नहीं लगाई और कृष्णा को रात में सोते से जगाकर आखिरी क्षणों में अपना नाम मंत्री की सूची में शामिल कराया। कुछ ऐसा ही दृढ़ संकल्प उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने में दिखाया और हर जोड़तोड़ आजमाने के बाद प्रतिद्वंद्वी सिद्धारमैया की जगह लेने जा रहे हैं।

डोड्डालाहल्ली केम्पेगौड़ा शिवकुमार का जन्म 15 मई, 1962 को कनकपुरा के एक संपन्न परिवार में हुआ था। 1980 के दशक में छात्र कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में पहला कदम रखा। 1985 के विधानसभा चुनाव में दिग्गज नेता एचडी देवेगौड़ा के सामने हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 1989 में महज 27 वर्ष की आयु में सथानूर निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। 2008 के बाद से वह कनकपुरा से चुनाव लड़ते रहे हैं।

2017 में उन्होंने विधायकों को पनाह दी तब आयकर अधिकारियों ने कई जगहों पर छापे मारे, जिनमें उनका अपना घर और उनके भाई व सांसद डीके सुरेश का घर भी शामिल था। उनके कारोबारी ठिकानों की भी तलाशी ली गई। दो साल बाद, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया; इस तरह वह कर्नाटक के पहले ऐसे प्रमुख राजनेता बन गए जिन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया। 50 दिनों बाद रिहा होने पर कांग्रेस के मजबूत चेहरे के तौर पर उनकी स्थिति और मजबूत हुई।

वहीं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धारमैया, जनता दल (सेक्युलर) नेता एचडी देवगौड़ा और भाजपा के बीएस येदियुरप्पा राज्य के अब तक के सबसे बड़े जननेताओं में गिने जाते हैं। सिद्धारमैया अपने जोशीले और ठेठ ग्रामीण हास्य से भरे भाषणों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने के मौके पर दिया गया उनका आखिरी सार्वजनिक भाषण उनके अपने मानकों के हिसाब से काफी फीका था। सिद्धरमैया का सियासी सफर विरोध और जुझारूपन की एक गाथा है। चुनौतियों को अवसरों में बदलने में माहिर सिद्धरमैया ने जदएस से अपने निष्कासन का इस्तेमाल कर्नाटक के पिछड़े समुदायों के एक लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरने के लिए किया। एजेंसी

सिद्धारमैया का जन्म 3 अगस्त, 1947 को मैसूर के पास सिद्धारमनहुंडी में हुआ था। वह कुरुबा समुदाय से आते हैं, जो एक पशुपालक समूह है और कर्नाटक की जाति व्यवस्था में पारंपरिक रूप से हाशिये पर रहा है। बीएससी और एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक लेक्चरर के तौर पर काम किया। 1983 में, उन्होंने लोक दल के टिकट पर चामुंडेश्वरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की।

जदएस से सिद्धारमैया को निकाला जाना निर्णायक मोड़ साबित हुआ। सिद्धारमैया ने कांग्रेस में शामिल होकर अपने साथ एक मजबूत जमीनी आधार और अहिंदा सम्मेलन (अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित) के जरिये माहौल बनाया, जिसने कर्नाटक में सामाजिक न्याय की अवधारणा को पूरी तरह से बदल दिया। न केवल कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकीहोली जैसे कद्दावर नेताओं ने पाला बदला, बल्कि क्षेत्रीय पार्टी के प्रति वफादार कई समुदायों ने भी अपनी निष्ठा सिद्धारमैया की ओर मोड़ ली।

जिम के कपड़ों से आने वाले बैक्टीरिया से कैसे बचें

हम आपको बता दें कि आपके पसीने से बदबू नहीं आती, लेकिन यह बैक्टीरिया त्वचा के संपर्क में आते हैं तो बदबू आने लगती है। हालांकि नए कपड़े पसीने को त्वचा से दूर करने में अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन इनमें बैक्टीरिया के पनपने की संभावना भी बढ़ जाती है। इससे बचने का एकमात्र तरीका है सफाई और सही रखरखाव।

तकनीकी कपड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले पॉलिएस्टर बैक्टीरिया को पसंद होते हैं। फाइबर की अद्वितीय बुनाई बैक्टीरिया को छिपने का स्थान देती है। यहां तक कि नियमित रूप से धोने के बाद भी बैक्टीरिया दूर नहीं होता। और चीजें निश्चित रूप से और भी खराब हो जाती है, अगर आप एक्सरसाइज के पसीने से तर कपड़ों को जिम बैग में रख देते हैं। चाहे फिर वह केवल कुछ घंटों के लिए ही क्यों न हो। अधिकांश लोगों को रखरखाव के स्तर का पता नहीं होता, जबकि इस नए मैटीरियल बदबू फ्री रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जिम जाने वालों को अपने पसीने से तर एक्सरसाइज के कपड़े क्लीनिंग के तीन स्टेप से साफ करें।

पहले खंगाले और फिर हवा में डालें

तत्काल ध्यान देना किसी भी समस्या की कुंजी होती है। वर्कआउट के कपड़ों को पानी से निकालकर तुरंत बाहर हवा में डाले। बाहर की ताजी और खुली हवा कपड़ों को न केवल सुखाएगी, बल्कि उनमें से बदबू भी हटा देगी। हालांकि तुरंत ऐसा करना अजीब लग सकता है, लेकिन यह पसीने और बैक्टीरिया को बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए एक्सरसाइज के बाद कपड़ों को बैग में रखना ठीक है, लेकिन घर जाने के तुरंत बाद इसे धोना सही रहता है। अगर घर जाते ही ऐसा करना संभव नहीं है तो कम से कम कपड़ों को शुष्क हवा में रख दें। कपड़े धोने के कमरे में फर्श पर नम कपड़ों का ढेर एक व्यवहार्य विकल्प नहीं है।

इन चीजों से पॉवर वॉश करें

धोने के पानी में 1 कप सफेद सिरका और 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिला दें। यह कपड़ों से बैक्टीरिया को दूर करने में मदद करता है। अगर फिर भी बदबू आ रही है तो कपड़ों को 1 कप सफेद सिरका, 2 चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 2 चम्मच बेकिंग सोडा वाले पानी में एक घंटे तक भिगोकर रख दें। फिर सफेद सिरके और बेकिंग सोडा के साथ धो लें।

अपने प्रयासों पर पानी मत डालें

जिम के कपड़ों के साथ फैब्रिक सॉफ्टनर और ड्रायर शीट के प्रयोग से बचें, क्योंकि यह कपड़ों पर कोटिंग छोड़ सकता है। और कभी-कभी अपने जिम बैग को भी धोना चाहिए क्योंकि इस बैग में जिम के लिए पानी की बॉटल, कपड़े, ग्लव्स, जूते, टॉवेल, आदि कई सामान होते हैं। आप इस बैग में पसीने वाले कपड़े भी रखते हैं। पसीने के कारण इनमें भी बैक्टीरिया पनपते हैं। इनके कारण ही त्वचा पर संक्रमण फैलने की अधिक संभावना होती है। इसके लिए सबसे पहले टैग की जांच करें, अगर आपका बैग मशीन में धो सकते हैं तो अंदर से बाहर मोड़कर, इसमें मौजूद किसी भी मैटल हिस्से को हटा दें। फिर इसे मशीन को डेलिकेट मोड पर करके धो लें और सुखाने के लिए हवा में बाहर डालें। लेकिन अगर आपका बैग चमड़े का है तो इसमें अखबार रखकर बदबू को बेअसर कर सकते हैं।

पेट के कैंसर से बचा सकता है बैंगनी आलू

बैंगनी आलू को अपने भोजन में शामिल कर आप पेट के कैंसर से बच सकते हैं। बैंगनी आलू पेट के कैंसर के लिए जिम्मेदार स्टेम कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं तथा इस घातक बीमारी को फैलने से रोकते हैं। अमेरिका की पेन्सिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में खाद्य विज्ञान के सहायक प्रोफेसर जयराम वानामाला ने बताया कि कैंसर का मुकाबला करने के लिए स्टेम कोशिकाओं पर हमला करना एक प्रभावी तरीका है।

क्यों आते हैं खर्राटे

कई बार वायुमार्ग के पास अतिरिक्त टिश्यू जमा हो जाते हैं जिससे वायु के प्रवाह में रुकावट आती है। इससे सांस सामान्य रूप से नहीं आता और खर्राटे की समस्या शुरू हो जाती है। वहीं खुले मुंह से खर्राटे लेने का संबंध गले के टिश्यू से हो सकता है। इसी तरह गर्भावस्था के दौरान भी गले में फैटी टिश्यू जमा होने के कारण कुछ महिलाएं खर्राटे लेती हैं। सर्दी या एलर्जी के कारण आने वाले खर्राटे अस्थायी होते हैं।

सामान्य डिलीवरी के लिए हैं ये योगासन

आज सामान्य और सेहतमंद तरीके से बच्चे को जन्म देना आसान नहीं है। इसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। आजकल का खानपान और व्यायाम के प्रति लापरवाही के चलते सामान्य डिलीवरी अब ना के बराबर हो गई है। इसी के चलते ज्यादातर महिलाओं को ऑपरेशन के द्वारा ही बच्चें को जन्म देना पड़ता है। जो महिला के स्वास्थ्य को कमजोर कर देती है। लेकिन अगर आप सामान्य रूप से डिलीवरी कराना चाहती है तो योगा के इन तीन आसान को नियमित रूप से करें।

पश्चिमोत्तानासन

- यह आसन स्त्रियों के लिए भी लाभकारी है। यह आसन गर्भाशय से सम्बन्धी शरीर के स्नायुजाल को ठीक करता है। इससे गर्भावस्था के दौरान रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी और कमर दर्द कम होगा। इससे तनाव कम होगा और मांसपेशियां लचीली होंगी।
- पैर सीधे करके बैठ जाएं और पंजों में हल्की दूरी रखें। अब गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को उठाएं और सांसे छोड़ते हुए पंजों को छूने की कोशिश करें। अधिक स्ट्रेस न लें और सांसे सामान्य कर लें। दस तक गिने और फिर सीधी अवस्था में आ जाएं। इसे अधिकतम तीन बार करें।
- इस स्थिति में आरामदायक समय तक श्वास-प्रश्वास सामान्य रखते हुए रुकें। इसके बाद श्वास अन्दर लेते हुए हाथ तथा धड़ को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं तथा श्वास बाहर निकालते हुए हाथ नीचे ले आएं। पश्विमोत्तानासन के अभ्यास के बाद रीढ़ को पीछे झुकाने वाले किसी भी आसन का अभ्यास करना चाहिए।

तितली आसन

- तितली आसन को गर्भावस्था के तीसरे महीने से कर सकते है। शरीर के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए यह आसन किया जाता है। यह गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के यूटेरस की मांसपेशियों को लचीला बनाता है और कमर को मजबूत करता है। इसे करने से शरीर के निचले हिस्से का तनाव खुलता है।

- तितली आसन करने के लिए दोनों पैरों को सामने की ओर मोड़कर, तलवे मिला लें, यानी पैरों से नमस्ते की मुद्रा बननी चाहिए। इसके पश्चात दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस करते हुए पैर के पंजे को पकड़ें और पैरों को ऊपर-नीचे करें। आपकी पीठ और बाजू बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस क्रिया को 15 से अधिक बार ना करे। यदि इस क्रिया को करते वक्त आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता हो तो इसे बिल्कुल भी न करें।

बद्ध कोणासन

- बिना ज्यादा तकलीफ के सामान्य डिलवरी कराने के लिए गर्भवती स्त्रियों को बद्ध कोणासन करना चाहिए। इस आसन से प्रसव पीड़ा कम होती है।
- समतल स्थान पर कंबल या अन्य कोई कपड़ा बिछाकर दोनों पैरों को सामने की ओर करके बैठ जाएं। फिर दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पैरों के पास ले आएं और दोनों पैरों के तलवें आपस में मिलाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ लें। पैरों की उंगुलियों को दोनों हाथों से पकड़ लें और रीढ़ को सीधा रखें जैसे तितली आसन में बैठा जाता है। बाजू को सीधा करें और पैरों को ज्यादा से ज्यादा पास लाने का प्रयास करें जिससे आपका शरीर तन जाए।
- यह इस आसन की प्रारंभिक स्थिति है। गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे कमर से आगे इस प्रकार झुकें कि रीढ और पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव बना रहे। प्रयास करें की आपका सिर जमीन से स्पर्श हो जाए। अगर ये संभव ना हो तो अपनी ठुड्डी को पैरों के अंगूठे से सांस को सामान्य कर लें। अंत में सांस भरते हुए वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। दो या तीन बार इस आसन का अभ्यास करें।

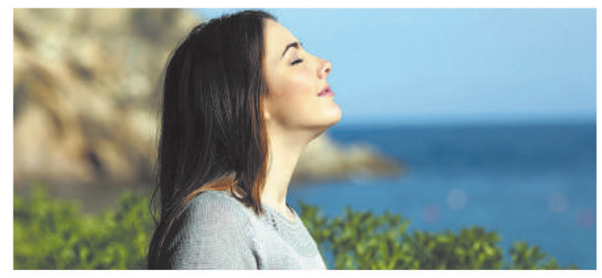

छोटी सांसें यानी ऑक्सीजन की कमी

खिलाड़ी व नियमित व्यायाम करने वालों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर नहीं जानते कि खून में पर्याप्त ऑक्सीजन का अच्छी फिटनेस से कितना गहरा संबंध है। शरीर में स्वस्थ कोशिकाएं एरोबिक होती हैं यानी उन्हें बढ़ने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जिस तरह बिना ऑक्सीजन आग नहीं जलती, उसी तरह हमारी कोशिकाएं भी बिना ऑक्सीजन ऊर्जाविहीन हैं। खून में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिमिया कहते हैं। ऐसा दमा, फेफड़े की बीमारी व शरीर में लोहतत्व की कमी पर भी होता है। सांसें छोटी आना, बेचैनी, सिरदर्द, उच्च रक्तचाप और त्वचा का नीला पड़ना भी खून में ऑक्सीजन की कमी से जुड़ा है। धमनियों में से खून के नमूने की जांच करके ऑक्सीजन का स्तर जांचा जाता है।

सेहत का मामला है

खून में पर्याप्त ऑक्सीजन होने से मेटाबॉलिक दर में भी वृद्धि होती है। वह दर, जिससे शरीर भोजन को ऊर्जा में बदलता है। खून में पर्याप्त ऑक्सीजन से कोशिकाओं में टॉक्सिन्स जमा नहीं होते। इतना ही नहीं, शरीर की एरोबिक क्षमता अधिक होने पर हृदय मजबूत होता है, फेफड़े ढंग से काम करते हैं और इम्युनिटी में सुधार होता है। अधिक श्रम के व्यायाम के लिए श्वसनतंत्र की मजबूती जरूरी है।

गहरे श्वास लेना है जरूरी

ऑक्सीजन सांस के जरिए शरीर में जाती है। हवा से ऑक्सीजन को अलग करने का काम फेफड़े करते हैं। ऑक्सीजन फेफड़ों के पास से रक्त नलिकाओं तक पहुंचती है और उसके बाद खून के जरिए कोशिकाओं तक। ऑक्सीजन का सही स्तर बनाए रखने के लिए जरूरी है गहरे श्वास लेना। अधिकतर रक्त नलिकाएं फेफड़ों के निचले हिस्से में होती हैं। छोटे श्वास लेने पर हवा केवल फेफड़ों के ऊपरी हिस्से तक ही पहुंचती है।

खानपान से ऐसे बढ़ाएं ऑक्सीजन

हरी सब्जियां जैसे चुकंदर, लहसुन, ब्रोकली, लेट्यूस, मूली व सीताफल का सेवन अधिक करें। फलों में स्ट्रॉबेरी व ऐवकाडो (रुचिरा) अधिक खाएं। इसके अलावा केला, आलू व टमाटर भी एसिडिटी को कम करते हैं और खून में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हैं।

- चुकंदर और लेट्यूस मिट्टी से नाइट्रेट अधिक ग्रहण करते हैं। पौधों से मिलने वाले नाइट्रेट, स्टोर किए गए मीट की तुलना में अधिक सेहतमंद हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी अधिक होते हैं। शरीर में पहुंच कर ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर नियमित होता है और कार्डियोवस्कुलर सिस्टम में सुधार होता है।
- भरपूर पानी व कच्ची हरी सब्जियों का जूस पिएं। यदि आपको अपनी सांसें असामान्य लगती हैं तो आप प्रतिदिन एक गिलास चुकंदर का जूस ले सकते हैं।
- इंटरवल एरोबिक ट्रेनिंग करें। यदि आप केवल चलते हैं तो इसे 40 मिनट की अवधि में पांच-पांच मिनट के इंटरवल में बांट लें। एक मिनट तेज गति से चलें और फिर चार मिनट धीमी गति से। ऐसा 5 से 6 बार दोहराएं।
- श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए नियमित वजन उठाएं, जिसमें कंधे, पीठ और छाती के व्यायाम शामिल हैं। इनसे श्वास की प्रक्रिया में सुधार होता है। गहरे श्वास लें।

इन तरीकों से धूम्रपान को कहें अलविदा

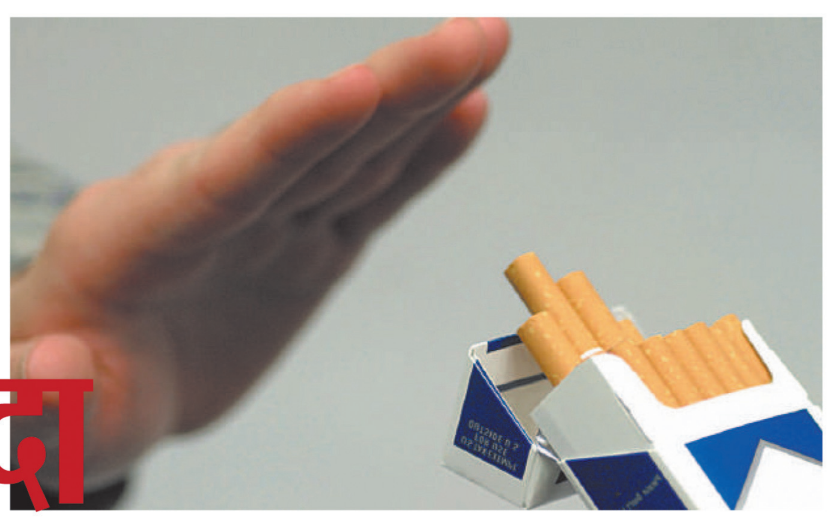

सिगरेट की लत के बारे में कहते है कि यह लगती तो आसानी है, लेकिन छूटती आसानी से नहीं है। लेकिन स्मोकिंग से होने वाले नुक्सानों को देखते हुए इसे छोड़ देना ही बेहतर है, और इस लत से छुटकारा भी पाया जा सकता है। बस, जरूरत है तो मजबूत इच्छाशक्ति की। धूम्रपान करने वालों को अक्सर लगता है कि अगर वे धुम्रपान छोड़ देंगे तो उनके जीवन की गुणवत्ता कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। जो लोग धूम्रपान से किनारा कर लेते हैं, वे धूम्रपान करने वालों की तुलना में कहीं ज्यादा संतुष्ट, स्वस्थ और खुश रहते हैं। यदि आप कुछ टिप्स आजमाएंगे तो यकीनन आप धूम्रपान की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। यहां हम बता रहे हैं आपको कुछ नुस्खे, जिससे आप अपनी आदत छोड़ सकते हैं।

आत्मसंयम

दृढ़ निश्चय के बाद दूसरी सबसे जरुरी चीज जो आपको चाहिए, वो है आत्मसंयम। यदि आप खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे तो सारा किया-धरा धुएं मे उड़ जाएगा। इसलिए आत्मनियंत्रण बहुत जरुरी है। हो सकता है शुरुआत मे दिक्कत आए, लेकिन खुद पर यकीन रखिए कि आप कर सकते हैं। आप अपने परिवार की एक ग्रुप फोटो अपने पास जरूर रखें। जब भी आप सिगरेट पीए, तो धुएं के आर-पार उस फोटो को देखें। धुएं के पार फोटो देखने से आपको लगेगा कि आप सिगरेट पी रहे है, लेकिन धुआं आपका परिवार झेल रहा है। यकीन मानिए धीरे-धीरे आपको अपनी सिगरेट पीने की आदत से चिढ़ होने लगेगी। कभी भी जल्दबाजी या आवेश मे आकर सिगरेट छोड़ने का फैसला न करें। यदि आप तैश मे आकर सिगरेट छोड़ने की कसम खाते हैं, तो यकीनन आपका दिमाग अगले ही पल कसम तोड़ने के बहाने तलाशने लगेगा। इसलिए सिगरेट छोड़ने का फैसला पूरे होश-ओ-हवास में करें।

सिगरेट को समय से जोड़े

अक्सर लोग जब खुश होते है तो सिगरेट पीते है, दुःखी होते है तो सिगरेट पीते है, टेंशन मे होते है तो पीते है। सबसे पहले तो आपको सिगरेट की फ्रिक्केंसी पर लगाम लगानी पड़ेगी। आठ घंटे या दस घंटे मे एक सिगरेट। यदि आप चेनस्मोकर है तो आठ घंटे की फ्रिक्केंसी सैट करिए और यदि आप दिन मे कभी कभार पीने वाले है तो 48 घंटे की फ्रिक्केंसी सही रहेगी। वैसे यह व्यक्ति दर व्यक्ति अलग हो सकती है। स्ट्रैस होने पर सिगरेट पीने का मन करता है। पहले अपने तनाव के कारण खोजें। उन पर विचार करके उनका हल तलाशें। यह सॉल्यूशन अपने मन पसंद कामों से हो सकता है। संगीत सुनना, खेलना, फिल्म देखना, किताबें पढ़ना, सैर-सपाटा या जो कुछ भी आपको पसंद हो, तनाव दूर करने के लिए करें। स्ट्रैस कम रहेगा तो तलब भी कम लगेगी।

ऐशट्रे को साफ मत करिए

आप जितनी चाहे सिगरेट पीजिए, लेकिन अपनी ऐशट्रे को साफ मत करिए, ये आपको याद दिलाती रहेगी कि आपने कितनी सिगरेट पी हैं। यदि आप अलग-अलग जगहों पर सिगरेट पीते है, तो आप बुझी सिगरेट की बट अपने साथ घर ले आएं और घर मे एक गिलास मे सारे बट डालकर रखें, ताकि आपको यह पी हुई सिगरेट की याद दिलाता रहे। जब भी आपके पास खाली समय हो आप इंटरनेट, अखबार या किताब में सिगरेट पीने के बुरे परिणामों वालों लेख जरूर पढ़ें। जिस दिन आप सिगरेट छोड़ने का मन बनाएं, उसी दिन अपना सिगरेट का पुराना स्टॉक सबसे पहले हटाएं। सिगरेट की तलब लगे, जाकर सिर्फ एक सिगरेट लेकर आएं और पीएं। प्रतिदिन पी जाने वाली सिगरेटों की संख्या कम करें। हर बार सिर्फ आधी ही सिगरेट पीएं। सिगरेट के किसी ऐसे ब्रांड को भी ट्राई कर सकते हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। यह भी आपको मदद करेगा।

रेसिपी

आलू पोस्तो

सामग्री

6-7 मध्यम आलू, 1 मध्यम प्याज, 2 हरी मिर्च, पंचफोरन मसाला 1 छोटा चम्मच, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, $1^{1/4}$ छोटा चम्मच नमक, 4 बड़े चम्मच पोस्ता दाना, 3 बड़े चम्मच तेल

विधि

प्याज का छिलका हटकट इसे धो लें। प्याज को बारीक टुकड़ों में काट लें। हरी मिर्च का डंठल हटा कर इसे धो लें। मिर्च को बारीक काट लें और अलग रखें। कटा प्याजः आलू को छीलकर इसे धो लें। अब हर आलू को 8 टुकड़ों में काट लें। कटे हुए आलू के टुकड़ेः कड़ाही में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें। गरम तेल में 1 छोटा चम्मच पंचफोरन मसाला डालें। जाम मसाले चटक जाएं और भुन जाएं तब इसमें कटी प्याज डालें। प्याज को गुलाबी होने तक भूनें। प्याज को भूनें में 2-3 मिनट का समय लगता है। अब भूनी प्याज में कटे आलू डालें। आलू को अच्छे से मिलते हुए दो मिनट के लिए भूनें। अब इसमें नमक डालें और आलू को थोड़ा गलने दे। इस प्रक्रिया में लगभग 5-6 मिनट का समय लगता है। यहां आलू को आधा ही गलाना है। आलू और प्याजः अब आलू में हल्दी पाउडर और कटी हुई हरी मिर्च डालें। अच्छे से मिलाएं और आलू के गलने तक पकाएं। हल्दी डालने के बादः जब तक आलू गल रहे हैं आप थोड़ा सा पानी डालकर पोस्ता दाना को बारीक पीस कर इसका पेस्ट बना लें। अब पोस्तो के पेस्ट को आलू में डालें। पोस्तो का पेस्ट डालने के बादः पोस्तो के पेस्ट को आलू में अच्छे से मिलाएं। अब एक चम्मच तेल डालें। सभी सामग्री को अच्छे से मिलाएं। ढकक्न लगाकर धीमी आंच पर पोस्तो आलू को दो मिनट पकने दें। आलू पोस्तोः आंच बंद कर दें अब, आलू पोस्तो तैयार है परोसने के लिए। आप इस स्वादिष्ट आलू पोस्तो को रोटी, पूरी, या फिर चावल किसी के साथ भी परोस सकते हैं।

मेवे के लड्डू

सामग्री

बादाम, अखरोट, पेकन 1 कप, काजू 1/4 कप, कटे हुए, खजूर 1 कप, क्रेनबेरी 2-3 बड़े चम्मच, हरी इलायची 4, ब्राउन शक्कर 2 बड़े चम्मच, पानी 1 बड़ा चम्मच, घी1 छोटा चम्मच (वैकल्पिक), कटे हुए मेवे

विधि

हरी इलायची की बाहरी छिलका निकालें और दानों को दरदरा कूट लें। मध्यम आंच पर कड़ाही में कटे हुए बादाम, पेकन, और अखरोट को 3-4 मिनट के लिए भूनें। अब इन्हे अलग रखें। काजू को भी मध्यम आंच पर 2 मिनट भूने और अलग रखें। खजूर के बीज हटाकर इसे बारीक काट लें। फिर से कड़ाही को गरम करें और इसमें दो बड़े चम्मच ब्राउन शुगर और एक चम्मच पानी गरम करें। जब शक्कर पिघल जाए और अच्छे से पानी के साथ मिल जाए तो इसमें कटे हुए खजूर को डालें। 2 मिनट में ही खजूर पिघलना शुरू कर देगा। खजूर के थोड़ा पिघलते ही इसमें भुने अखरोट, काजू, पेकान, और बादाम डालें। अब इलेयची पाउडर डालें। इसे बराबर चलाते हुए मेवे को खजूर के साथ 2-3 भूनें। अब इसमें क्रेनबेरी डालें। अच्छे से सभी सामग्री को मिलाएं। अब अगर आप चाहें तो जरा सा (1 छोटा चम्मच) घी दल सकते हैं इस मिश्रण में खुशबू के लिए। अब आंच बंद कर दें और लड्डू के मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें। अब लगभग 1 बड़ा चम्मच मिश्रण लें और उसे गोल लोग घूमते हुए लड्डू बांधें। इसी प्रकार सारे लड्डू बना लें। स्वादिष्ट मेवे के लड्डू अब तैयार हैं। आप इन लड्डू को हफ्ते भर फ्रिज के बाहर रख सकते हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

नीट पेपर मामला: जिम्मेदारी कौन लेगा: पवन खेड़ा

नई दिल्ली। नीट-यूजी 2026 पेपर लीक और परीक्षा रद्ध मामले को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए परीक्षा प्रणाली में बार-बार सामने आ रही गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि जब परीक्षा से जुड़ा कोई बड़ा विवाद सामने आता है, तभी सरकार और प्रधानमंत्री निगरानी की बात करते हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि यदि परीक्षा प्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और पेपर लीक जैसी घटनाएं दोहराई जा रही हैं, तो इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित होना आवश्यक है। कांग्रेस नेता ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी घेरते हुए कहा कि यदि परीक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियां सामने आई हैं, तो इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि परीक्षा सुरक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधनों या संस्थाओं की मदद ली जा रही है।

शिक्षा व्यवस्था माफिया के चंगुल में :केजरीवाल

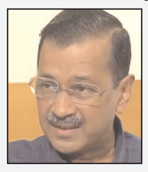

नई दिल्ली। पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नीट-यूजी परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए वायुसेना के विमानों के इस्तेमाल संबंधी प्रस्तावित व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केवल प्रश्नपत्रों के परिवहन का तरीका बदलने से पेपर लीक जैसी समस्याएं खत्म नहीं होंगी और इसके लिए मजबूत एवं पारदर्शी व्यवस्था की आवश्यकता है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी अपने बयान में केजरीवाल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पेपर लीक रोकने की बजाय दिखावटी उपायों पर केंद्रित दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था परीक्षा माफिया के प्रभाव में आ चुकी है और इसे सुधारने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयासों की जरूरत है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित नीट-यूजी परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने के बाद रद्द कर दी गई थी।

'वंदे मातरम्' प्रोटोकॉल का पालन न करने से केरल के राज्यपाल नाराज

तिरुवनंतपुरम। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इस बात पर नाराजगी जताई कि जब वह संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार के नीतिगत अभिभाषण के लिए विधानसभा में मौजूद थे, तब 'वंदे मातरम्' पूरा नहीं गाया गया। उन्होंने कहा कि जब राज्यपाल ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थित हों, तब उचित प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। केरल विधानसभा में राज्यपाल के नीतिगत अभिभाषण से पहले और बाद में एक बैंड दल ने 'वंदे मातरम्' के शुरुआती अंतरे प्रस्तुत किए।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा से लौटने के बाद लोक भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह पहले से तय था कि जब भी राज्यपाल सदन में मौजूद हों, तब 'वंदे मातरम्' पूरा गाया जाए। उन्होंने कहा कि विधानसभा में गीत केवल बजाया गया, गाया नहीं

सड़कों पर उतरी कॉकरोच जनता पार्टी

नई दिल्ली। देश के युवाओं ने अब जर्जर बुनियादी ढांचे और नागरिक समस्याओं के खिलाफ अपना रोष प्रकट करने का अनोखा और व्यंग्यात्मक तरीका ढूंढ लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी कॉकरोच जनता पार्टी अब सड़कों पर उतर आई है। उनका पहला ग्राउंड कैंपेन इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है और नगर निगमों की कार्यप्रणाली पर सीधा प्रहार कर रहा है। इस कैंपेन के तहत कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक देशभर में पोटहोल्स, कूड़े के ढेर, टूटे स्ट्रीटलाइट्स, सरकारी दफ्तरों में लापरवाही और अन्य नागरिक समस्याओं को रिकॉर्ड करके पार्टी को टैग कर रहे हैं। पार्टी का दावा है कि ये वीडियो और तस्वीरों को अम्प्लिफाई करके प्रशासन पर दबाव बनाया जाएगा। अभिजीत दीपके नामक व्यक्ति द्वारा शुरू की गई इस ऑनलाइन कॉकरोच जनता पार्टी ने एक वीडियो शेयर किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस तीन मिनट के वीडियो में एक व्यक्ति कॉकरोच के आकार का मुखौटा पहनकर शहर की सड़कों और नालियों के आसपास दिखाई देता है।

ऐसे कायराना हमलों से डरने वाले नहीं : टीएमसी सांसद

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर इलाके में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेके जाने और हमला करने से राजनीतिक माहौल गरमा गया है। आरोप है कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक पर जानलेवा हमला किया गया, वे चुनावी हिंसा में घायल पार्टी कार्यकर्ताओं का हाल जानने पहुंचे थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सांसद अभिषेक बनर्जी सोनारपुर में हाल ही में हुई चुनावी हिंसा में घायल हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने और उनका हालचाल जानने पहुंचे हुए थे। इसी बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया और देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है, जैसे ही अभिषेक का काफिला सोनारपुर पहुंचा, वहां पहले से ही मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी, और देखते ही देखते हिंसक झड़प शुरु हो गई। भीड़ में से ही कुछ ने सांसद पर अंडे फेंके और उनके साथ धक्का-मुक्की भी की, जिससे अभिषेक की शर्ट फट गई।

हेलमेट पहना सुरक्षित बाहर निकाला

देशभर में 1 जून से चलेगा 'खेत बचाओ अभियान

कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने की तैयारियों की समीक्षा

नई दिल्ली। किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से केंद्र सरकार 1 जून से 30 जून 2026 तक देशव्यापी 'खेत बचाओ अभियान' शुरू करने जा रही है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह केवल जागरूकता कार्यक्रम नहीं, बल्कि खेतों और मिट्टी को बचाने का जन आंदोलन होगा।

दिल्ली में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य कम खाद, सही खाद और सही सलाह के सिद्धांत को किसानों तक पहुंचाना है। इसके तहत रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग को कम करने, मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा देने तथा जैविक एवं जैव-उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अभियान पंचायत स्तर से संचालित होगा और इसमें पंचायतों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), राज्य सरकारों तथा जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम गांवों की जरूरतों और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संचालित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बदलते मौसम और कृषि क्षेत्र की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों को मौसम, मिट्टी और बाजार की स्थिति के अनुसार व्यावहारिक सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। फसल विविधीकरण, कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा और जोखिम प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

16 सौ से अधिक टीमों का गठन

बैठक में जानकारी दी गई कि अभियान के सफल संचालन के लिए 1600 से अधिक टीमों का गठन किया गया है। इनमें 100 से अधिक उर्वरक उपयोग वाले जिलों में कार्य करने वाली 500 विशेष टीमें शामिल हैं। इसके अलावा केवीके और आईसीएआर की 1150 से अधिक टीमें भी किसानों तक पहुंचकर तकनीकी मार्गदर्शन देंगी। अभियान के दौरान मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम-किसान योजना के छूटे लाभार्थियों का पंजीकरण, दलहन-तिलहन मिशन, कृषि यंत्रीकरण और जल संरक्षण जैसी गतिविधियां भी चलाई जाएंगी। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दें और खेत स्तर पर सकारात्मक बदलाव सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य खेतों को बचाना, लागत कम करना, मिट्टी को स्वस्थ बनाना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है।

पंजाब नगर निकाय चुनावों में हार पर मचा घमासान

पंजाब कांग्रेस की बैठक में राहुल और खड़गे के सामने भिड़े नेता

नईदिल्ली। पंजाब नगर निकाय चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इससे राज्य इकाई के भीतर के मतभेद खुलकर सामने आ गए, क्योंकि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर आयोजित इस उच्च स्तरीय रणनीति बैठक में राहुल गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और पंजाब के प्रमुख नेता उपस्थित थे। पार्टी के नगर निगम चुनाव प्रदर्शन पर चर्चा जल्द ही विवादों में घिर गई, जिसमें नेताओं ने चुनावी परिणामों और संगठनात्मक जिम्मेदारियों दोनों पर सवाल उठाए। खबरों के मुताबिक, सबसे तीखी बहस गिद्दरबाहा में पार्टी के खराब प्रदर्शन पर केंद्रित थी, जिसे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग का राजनीतिक गढ़ माना जाता है।

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कथित तौर पर सवाल उठाया कि पार्टी राज्य अध्यक्ष के गढ़ में इतना खराब प्रदर्शन कैसे कर सकती है, जबकि वह 2027 के विधानसभा चुनावों में खुद को एक मजबूत दावेदार के रूप में पेश कर रही है। सूत्रों के अनुसार, चन्नी ने तर्क दिया कि अगर पार्टी इतने महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में परिणाम देने में विफल रही है, तो उसे गहन आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। वारिंग ने कथित तौर पर नतीजों का बचाव करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को नगर निगम चुनावों के दौरान सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल से फायदा हुआ था। हालांकि, एक अन्य वरिष्ठ नेता ने इस स्पष्टीकरण को चुनौती देते हुए कहा कि समान राजनीतिक परिस्थितियों में भी कांग्रेस ने कपूरथला और चमकौर साहिब जैसे स्थानों पर

महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी।

बैठक के दौरान चन्नी की नगर निगम चुनाव प्रचार में सीमित भागीदारी पर भी सवाल उठाए गए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर विदेश में व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं को प्रचार के एक महत्वपूर्ण चरण में अपनी अनुपस्थिति का कारण बताया। राज्य नेतृत्व में मतभेदों की अटकलों को और हवा देते हुए, पंजाब के विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा बैठक समाप्त होने से पहले ही चले गए। हालांकि, कांग्रेस पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल ने बाद में किसी भी असहमति की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि बाजवा ने नेतृत्व को पहले ही सूचित कर दिया था और उनके जल्दी चले जाने को कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

बैठक में हुई बहस में नगर निगम चुनावों में पंजाब के मतदाताओं के मिले-जुले फैसले की झलक दिखी। पंजाब राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 1,977 वार्डों के 1,963 घोषित परिणामों में से आम आदमी पार्टी ने 954 वार्ड, कांग्रेस ने 390, निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251, एसएडी ने 191, भाजपा ने 170 और बीएसपी ने सात वार्ड जीते। कपूरथला नगर निगम में कांग्रेस ने 50 में से 31 वार्ड जीतकर शानदार जीत हासिल की और स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, जबकि अन्य क्षेत्रों में पार्टी को संघर्ष करना पड़ा।

सीयूईटी को लेकर राहुल गांधी का पीएम पर तंज

दावे विश्वगुरु के, लेकिन एक भी परीक्षा ढंग से नहीं करा सकते

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विश्वगुरु बनने के बड़े-बड़े दावे करने वाली सरकार एक भी परीक्षा को ठीक से आयोजित कराने में सक्षम नहीं है।

राहुल गांधी की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने बताया कि शनिवार को देश भर के स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित सीयूईटी-यूजी 2026 परीक्षा कुछ केंद्रों पर तकनीकी खराबी के कारण देरी से शुरू हुई।

कांग्रेस नेता ने एक्स पर कहा, नीट, सीबीएसई, एसएससी और आज सीयूईटी। चार परीक्षाएं। बच्चे। एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के अंदर एक भी परीक्षा ढंग से आयोजित नहीं हो पा रही है। वहीं, विश्वगुरु बनने के दावे किए जा रहे हैं।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता आगे कहा, जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।

कांग्रेस नेता ने शुक्रवार को यह भी कहा था कि सीबीएसई की परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर प्रधानमंत्री का मौन

और शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई न होना, यह दर्शाता है कि उन्हें केवल अपनी सरकार बचाने की चिंता है, न कि लाखों छात्रों के भविष्य की।

राहुल गांधी ने इससे पहले उन छात्रों के साथ अपनी एक बातचीत का वीडियो भी साझा किया था, जिन्होंने नीट परीक्षा दी थी और पेपर लीक की घटनाओं के मद्देनजर परीक्षा प्रणाली को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की थीं। उन्होंने कहा था कि नीट छात्रों से मुलाकात में एक बात बिल्कुल साफ हो गई- भारत का युवा नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं करता।

लोकसभा में नेता विपक्ष ने कहा, उन्होंने मुझे बताया- पेपर वॉट्सएप और टेलीग्राम पर खुलेआम बिक रहे हैं। किस कीमत पर बिक रहे हैं, कौन खरीद रहा है, माफिया कैसे काम कर रहे हैं - यह सब इन बच्चों को पता है। उनका एक ही सवाल था - जो हमें पता है, वो सरकार और संस्थाओं को क्यों नहीं? सच यह है ये बच्चे सरकार से बेहतर जानते हैं कि इस सड़ी हुई व्यवस्था को कैसे ठीक किया जा सकता है।

खेल
प्रमुख समाचार

फ्रेंच ओपन से नोवाक जोकोविच हुए बाहर

पेरिस। फ्रेंच ओपन 2026 में एक और बड़ा उलटफेर देखने को मिला। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच तीसरे दौर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ब्राजील के 19 वर्षीय खिलाड़ी जोआओ फोंसेका ने दो सेट से पिछड़ने के बावजूद शानदार वापसी करते हुए जोकोविच को 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 से मात दी।

करीब चार घंटे 53 मिनट तक चले इस मुकाबले में फोंसेका ने असाधारण मानसिक मजबूती दिखाई। वह ग्रैंड स्लैम मुकाबले में नोवाक जोकोविच को हराने वाले पहले किशोर खिलाड़ी बन गए। इसके साथ ही उन्होंने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ऐतिहासिक जीत के बाद फोंसेका ने कहा, मैं सिर्फ जितना संभव हो सके उतनी ताकत से गेंद को हिट करने की कोशिश कर रहा था। जोकोविच बहुत कम गलतियां करते हैं और हमें आज भी लगता है कि वह 20 साल के खिलाड़ी की तरह खेलते हैं।

रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब की तलाश में उतरे जोकोविच ने हार के बाद अपने युवा प्रतिद्वंद्वी की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा, जीत का पूरा श्रेय जोआओ को जाता है। उन्होंने महत्वपूर्ण मौकों पर मुझसे बेहतर टेनिस खेली और जीत के सही हकदार थे। जोकोविच के बाहर होने से एक दिन पहले दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी यानिक सिनर भी दूसरे दौर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। वहीं मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कारेज चोट के कारण पहले ही नाम वापस ले चुके थे। ऐसे में अब यह तय हो गया है कि फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग को नया ग्रैंड स्लैम चैंपियन मिलेगा।

दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने क्वेंटिन हेलिस को 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 से हराकर चौथे दौर में जगह बनाई।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान
प्रमुख समाचार

तेल कंपनियों को 30 दिनों का एलपीजी बैकअप रखने का आदेश

नईदिल्ली। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सरकारी तेल कंपनियों को आदेश दिया है कि वे भविष्य की किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कम से कम 30 दिनों का एलपीजी रिजर्व स्टॉक यानी बैकअप तैयार रखें। ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में देश में गैस की किल्लत न हो। इसके साथ ही सरकार कच्चे तेल का भी अतिरिक्त स्टॉक बनाने पर काम कर रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। फरवरी में जो कच्चा तेल भारत को 69.01 डॉलर प्रति बैरल मिल रहा था, वह मई में बढ़कर 106.83 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। इस बढ़ोतरी के कारण भारतीय तेल कंपनियों को हर दिन लगभग 550 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।

मुंबई में सीएनजी की कीमतें 2 रुपये बढ़ी

मुंबई। मुंबईवासियों को अब सीएनजी और पीएनजी गैस के लिए ज्यादा दाम चुकाना होगा। क्योंकि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) 2 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है, जबकि घरों में इस्तेमाल होने वाली पाइप वाली नेचुरल गैस (पीएनजी) की कीमत 50 पैसे प्रति एससीएम (स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर) बढ़ा दी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद ऑटो-रिक्शा और टैक्सी यूनियनों ने किराए में बदलाव की नई मांगें उठाई हैं। इस ताजा बदलाव के बाद सीएनजी की खुदरा कीमत 84 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 86 रुपये प्रति किलो हो गई है। अब मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और महानगर गैस लिमिटेड के दायरे में आने वाले आस-पास के इलाकों में घरों में इस्तेमाल होने वाली पीएनजी की कीमत 52 रुपये प्रति एससीएम होगी। पिछली बढ़ोतरी 13-14 मई को लागू हुई थी।

आरबीआई की विदेशी मुद्रा से लेनदेन आय 52 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की विदेशी मुद्रा लेनदेन से आय वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 1.69 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 52 प्रतिशत अधिक है। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। आरबीआई ने 2024-25 में विदेशी मुद्रा लेनदेन से 1.11 लाख करोड़ रुपए का विनिमय लाभ अर्जित किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि 31 मार्च 2026 तक आरबीआई का कुल बहीखाता आकार 15.72 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 91.97 लाख करोड़ रुपए हो गया। परिसंपत्ति पक्ष पर वृद्धि घरेलू निवेश, स्वर्ण भंडार और विदेशी निवेश में क्रमश: 44.9 प्रतिशत, 63.8 प्रतिशत और 7.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी के कारण दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2025-26 में आरबीआई का अधिशेष बढ़कर 2,86,588.46 करोड़ रुपए हो गया, जो 2024-25 में 2,68,590.07 करोड़ रुपए था।

1,62,800 रुपए के पार पहुंचा 10 ग्राम सोना

नईदिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1,600 रुपए बढ़कर 1.62 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। यह तेजी, मजबूत वैश्विक रुख, अमेरिका-ईरान के बीच शुरुआती समझौते की संभावना और घरेलू बाजार में शादी-ब्याह की मांग की उम्मीदों के कारण आई है। स्थानीय बाजार के जानकारों के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,600 रुपए बढ़कर 1,62,900 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गई। बुधवार को बाजार बंद होने के समय इसकी कीमत 1,61,300 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। चांदी की कीमत भी 5,000 रुपए मजबूत होकर 2,74,700 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई। पिछले सत्र में चांदी की कीमत 2,69,700 रुपए प्रति किलोग्राम थी।

शेयर बाजार में भारतीय निवेशकों के 13 लाख करोड़ डूबे

सनत जैन

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो ताजा रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उसके अनुसार भारतीय शेयर बाजार में पिछले तीन माह में भारी उतार चढ़ाव के कारण निवेशकों के 13 लाख करोड रुपए शेयर बाजार में डूब गए हैं। चौथी तिमाही में निफ्टी 50 में 10 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। भारतीय शेयर बाजार में जिस तरह की गिरावट निरंतर बनी हुई है। उसने भारत के संस्थागत निवेशक वित्तीय संस्थान बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम की चिंताऐं तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरह से तनाव बना हुआ है। यह आगे और बढ़ता हुआ दिख रहा है। दुनिया के अधिकांश देशों में ऊर्जा संकट लगातार बढ़ रहा है। ऊर्जा संकट के कारण अर्थव्यवस्था में भारी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। ऊर्जा संकट ने पूरी दुनिया में एक अलग तरह के आर्थिक संकट को जन्म दिया है। कच्चे तेल और गैस इत्यादि के बढ़ते दाम, उपलब्धता में लगातार कमी से शेयर बाजारों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। विदेशी निवेशक भारत से अपना निवेश निकलकर भाग रहे हैं। 2026 एनएसई की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है।उसके अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों में घरेलू निवेशकों की कुल हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। विदेशी निवेशक लगातार कई वर्षों से मुनाफा वसूली कर रहे थे। भारत का पैसा मुनाफे के रूप में विदेशों में चला गया है। विदेशी निवेश लगातार निकलने के कारण वहीं विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी न्यूनतम स्तर पर आ गई है। लगातार गिरावट के कारण भारत में घरेलू निवेशकों का फंड घटकर 76. 5 लाख करोड रुपए रह गया है. पिछली तिमाही के आधार पर लगभग 13 फ़ीसदी की गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार विदेशी

पोर्टफोलियो में निवेशकों ने 19.6 अरब डॉलर भारतीय शेयर बाजार से निकाल लिए हैं। सूचीबद्ध कंपनियों में विदेशी निवेशको की हिस्सेदारी घटकर 17 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। जो वर्तमान में चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गया है। शेयर बाजार के साथ-साथ विदेशी मुद्रा का संकट भी भारत में बढ़ता चला जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिर रही है। कच्चे तेल और गैस की कीमतें बढ़ने और डॉलर मुद्रा में भुगतान के कारण आर्थिक स्थिति में बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। चीन से आयात की तुलना में निर्यात बहुत कम है।युवान मुद्रा को लेकर भी लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था संकट में फंसती चली जा रही है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है, डॉलर से ज्यादा खराब स्थिति युवान के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को झेलना पड़ रही है। चीन से भारत का आयात निर्यात में अंतर बढ़ता चला जा रहा है। राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था दो पाटों के बीच में फंसकर रह गई है। डॉलर और युवान दोनों ही भारत के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। जिस तरह की स्थिति वर्तमान में बन रही है। उसने सभी अर्थशास्त्रियों को चिंता में डाल दिया है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें चार बार बढ़ा दी गई हैं। इसका असर महंगाई पर पड़ रहा है। महंगा डीजल पेट्रोल महंगाई को बढ़ाने का काम कर रहा है। सरकार ने औद्योगिक कंपनियों के लिए डीजल का रेट बढ़ाकर 149 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 54 रुपए प्रति लीटर ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। इसका असर सभी उत्पाद पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था का संकट सभी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। शेयर बाजार और भारतीय अर्थव्यवस्था में जिस तरह की नकारात्मकता देखने को मिल रही है। उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है। सरकार ने वास्तविकता को स्वीकार करते हुए यदि कठोर निर्णय नहीं लिए तो स्थिति बद से बदतर हो सकती है। केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को स्थितियों का मुकाबला करने के लिए जिस तरह के प्रयास करने चाहिए, उस तरह के प्रयास कहीं से भी होते हुए नही दिख रहे हैं। उल्टा सरकार वर्तमान स्थिति का मुकाबला आंख मूंदकर, भगवान भरोसे संकट के समय मुंह मोड़ रही है। उसके कारण स्थिति दिनों दिन खराब हो रही है।

पत्रकार लोकतंत्र के सच्चे सेनानी: सीएम साय

रायपुर । पत्रकार लोकतंत्र के सच्चे सेनानी हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर परिश्रम करते हुए सूचनाओं को जन-जन तक पहुंचाते हैं और समाज को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीडिया की सकारात्मक आलोचना केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि प्रशासन और सरकार को भी आत्ममंथन और बेहतर कार्य की दिशा प्रदान करती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर परिसर के सुंदर सदन में आयोजित पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव को संबोधित करते हुए यह बात कही। यह आयोजन हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित किया गया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि माता कौशल्या की धरती और भगवान श्रीराम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता की गौरवशाली परंपरा पर आधारित ऐसा अद्भुत आयोजन निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। उन्होंने आयोजन के लिए रायपुर प्रेस क्लब को बधाई देते हुए कहा कि रायपुर प्रेस क्लब देश के पुराने और प्रतिष्ठित प्रेस क्लबों में से एक है, जिसका इतिहास समृद्ध और प्रेरणादायी रहा है।

उन्होंने कहा कि पत्रकारिता और पत्रकारों के सम्मान में आयोजित ऐसे कार्यक्रम प्रेस क्लब की प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता का सशक्त प्रमाण हैं।

मुख्यमंत्री साय ने रायपुर की पत्रकारिता परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि इस शहर ने पत्रकारिता जगत को अनेक शिखर पुरुष दिए हैं। उन्होंने मधुकर खेर, मायाराम सुरजन, ललित सुरजन, रमेश नैय्यर और बबन प्रसाद मिश्र सहित अनेक प्रतिष्ठित संपादकों और पत्रकारों का स्मरण करते हुए कहा कि इन विभूतियों ने पत्रकारिता की सशक्त और वैचारिक परंपरा को समृद्ध किया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र की आधारशिला है और देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन तक पत्रकारिता ने हमेशा परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि 30 मई 1826 को कोलकाता से जुगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित देश के प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड ने भारतीय पत्रकारिता की मजबूत नींव रखी। हिंदी पत्रकारिता के दो सौ वर्षों की यह गौरवशाली यात्रा देशवासियों के लिए गर्व का विषय है।

मुख्यमंत्री ने भारतीय सनातन परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि देवर्षि नारद को आदि पत्रकार माना जाता है और इसी कारण पत्रकार बंधु नारद जयंती को सम्मानपूर्वक मनाते हैं। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत रोचक और प्रेरक तथ्य है कि उदंत मार्तंड का प्रकाशन भी नारद जयंती के दिन आरंभ हुआ, जो इस बात का प्रतीक है कि भारतीय पत्रकारिता की जड़ें हमारी सांस्कृतिक चेतना और सनातन मूल्यों से गहराई से जुड़ी रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय पत्रकारिता ने राष्ट्रवादी चेतना को स्वर देने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, माधवराव सप्रे और सुभाषचंद्र बोस सहित अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने पत्रकारिता को सामाजिक जागरण और राष्ट्रीय चेतना के माध्यम के रूप में उपयोग किया। उन्होंने कहा कि जब भी भारतीय पत्रकारिता का गौरवशाली इतिहास लिखा जाएगा, तब छत्तीसगढ़ का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। उन्होंने मां भारती के सपूत माधवराव सप्रे का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ मित्र का संपादन कर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों को जागृत और संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पत्रकारिता की चर्चा जब भी होगी, तब भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण स्वाभाविक रूप से होगा। उन्होंने कहा कि अटल जी ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय चेतना की जो अलख जगाई, उसने स्वतंत्र भारत में लाखों लोगों को प्रेरित किया।

छत्तीसगढ़ का स्मार्ट पंजीयन मॉडल बना सुशासन की नई पहचान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सुशासन और नागरिक सुविधाओं को केंद्र में रखकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। इसी दिशा में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में पंजीयन विभाग में ऐतिहासिक एवं परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार का उद्देश्य पंजीयन प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी, तकनीक आधारित तथा नागरिकों के लिए पूरी तरह सुविधाजनक बनाना है। कभी लंबी कतारों, घंटों इंतजार, दस्तावेजों के सत्यापन में देरी और बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने वाली पंजीयन प्रक्रिया अब पूरी तरह बदलती दिखाई दे रही है। पहले जहां एक साधारण रजिस्ट्री पूरी करने में 4 से 6 घंटे अथवा कई बार 1 से 2 दिन तक लग जाते थे, वहीं अब आधुनिक डिजिटल व्यवस्थाओं की मदद से यही प्रक्रिया केवल 15 से 20

मिनट में पूरी हो रही है। इससे नागरिकों के समय, धन और ऊर्जा तीनों की बड़ी बचत हो रही है।

राज्य सरकार ने अगले एक वर्ष के भीतर प्रदेश के सभी 119 पंजीयन कार्यालयों को स्मार्ट एवं विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पहले चरण में नवा रायपुर सीबीडी बिल्डिंग, बेबीलॉन टॉवर रायपुर, श्रीराम बिजनेस पार्क, सड्डू, कलेक्ट्रेट परिसर रायगढ़, दुर्ग, बिलासपुर, कुनकुरी, अभनपुर तथा तिल्दा सहित 10 प्रमुख कार्यालयों को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। इन नए स्मार्ट पंजीयन कार्यालयों में अब नागरिकों को वेटिंग लाउंज, वातानुकूलित सुविधा, स्वच्छ एवं व्यवस्थित परिसर, नि:शुल्क वाई-फाई, मोबाइल चार्जिंग स्टेशन, शुद्ध पेयजल, आधुनिक शौचालय, हेल्प डेस्क तथा प्री-प्रेजेंटेशन काउंटर जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। इससे पंजीयन कार्यालय अब किसी आधुनिक सेवा केंद्र की तरह दिखाई देने लगे हैं।रायगढ़ के लाभार्थी श्री आशीष अग्रवाल ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि, पहले यहां आने पर निराशा महसूस होती थी, लेकिन अब माहौल पूरी तरह बदल गया है।

एनआईटी रायपुर में 66 करोड़ की नई परियोजनाओं का शुभारंभ

रायपुर। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर में गुरुवार को शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता तथा सतत विकास से जुड़ी सात महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास समारोह आयोजित किए गए। इन परियोजनाओं के माध्यम से संस्थान की शैक्षणिक, अनुसंधान एवं नवाचार संबंधी क्षमताओं को नई मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉ. सुरेश हावरे ने की। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉ. एन. वी. रमना राव, डीन, प्राध्यापकगण, कर्मचारी, छात्र, पूर्व छात्र एवं अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

समारोह में चार नई सुविधाओं का उदघाटन तथा तीन प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास किया

गया। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 तथा 'विकसित भारत-2047' की परिकल्पना के अनुरूप उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

कार्यक्रम के दौरान गोल्डन टॉवर की दूसरी मंजिल पर लगभग 5,500 वर्गफुट क्षेत्र में विकसित एनआईटी रायपुर एफआईई इनक्यूबेशन सेंटर का उदघाटन किया गया। लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से स्थापित यह छत्तीसगढ़ का पहला विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) समर्थित टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर है। वर्तमान में यह केंद्र क्लीन-टेक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा बहुविषयक तकनीकी एकीकरण से जुड़े 50 से अधिक स्टार्टअप्स को सहयोग प्रदान कर रहा है।

इसके साथ ही गोल्डन टॉवर के सामने सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ भी किया गया। विद्युत मंत्रालय की रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल योजना के अंतर्गत स्थापित इस सुविधा में 60 किलोवाट क्षमता तक के दो एसी/डीसी चार्जर लगाए गए हैं। यह परियोजना स्वच्छ एवं पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।समारोह में गोल्डन टॉवर के समीप उच्च-वोल्टेज इम्पल्स परीक्षण प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखी गई।

सीएम हेल्पलाइन के प्रभावी संचालन हेतु अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण

रायपुर। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला कार्यालय कोंडागांव के सभाकक्ष में शनिवार को एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना, जिला पंचायत सीईओ श्री अविनाश भोई, अपर कलेक्टर श्री चित्रकांत चाली ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण के दौरान सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सलाहकार श्री अशोक चौबे एवं प्रशिक्षक श्री पवन तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन प्रणाली पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इनमें यूनिक टोकन नंबर के माध्यम से शिकायतों की ट्रैकिंग, समयबद्ध निराकरण के लिए एसएलए आधारित व्यवस्था, समाधान उपरांत नागरिकों से संतुष्टि फीडबैक, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा तथा एमआईएस डैशबोर्ड के जरिए सतत निगरानी शामिल है। उन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाइन कॉल सेंटर 24 घंटे संचालित रहेगा और नागरिक टोल फ्री नंबर 1076 के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे तथा उसकी स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी जानकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचेगी।

आमों की सुगंध और स्वाद से सराबोर हुआ रायपुर

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव में आमों की सुगंध और स्वाद से रायपुर शहर सराबोर हो गया है। महोत्सव के दूसरे दिन बड़ी संख्या में आम प्रेमी एवं दर्शक पहुँचे। आगंतुकों ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित आम की विभिन्न दुर्लभ, लोकप्रिय एवं उन्नत किस्मों का अवलोकन कर उनकी विशेषताओं, स्वाद, रंग, आकार एवं उत्पादन संबंधी जानकारी प्राप्त की। प्रसिद्ध शेफ आकांक्षा रॉय द्वारा आम प्रेमियों को आमों के विभिन्न व्यंजनों की रेसिपी सिखाई गई। उनके द्वारा बनाये गए आमों के विभिन्न व्यंजनों ने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। आम महोत्सव में विभिन्न राज्यों से आए आम उत्पादक कृषक द्वारा आम की विविध

किस्मों के फलों का विक्रय किया जा रहा है। विक्रय स्टॉलों पर भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। आगंतुकों ने अपनी पसंदीदा किस्मों के आमों की खरीदारी की। अल्फांसों, केसर, दशहरी, फज़ली और अरूणिमा किस्मों की अधिक मांग रही। महोत्सव में आम की विविधता, स्वाद और कृषि नवाचारों को करीब से जानने का अवसर मिलने से दर्शकों में विशेष उत्साह देखा गया। यह आयोजन आम उत्पादकों, उद्यमियों एवं आम प्रेमियों के लिए ज्ञान, व्यापार और स्वाद का एक अनूठा मंच बनकर उभर रहा है।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव के द्वितीय दिवस तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कृषकों ने भाग लिया। सत्र के दौरान विशेषज्ञों ने आम की खेती से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

आरोपी विधायक के साथ होना हिंसक चरित्र: दीपक बैज

रायपुर। अधिकारी के साथ मारपीट करने वाले विधायक रामकुमार टोप्पो के साथ भाजपा के खड़े होने के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा ने विधायक रामकुमार टोप्पो के साथ खड़ा होने का बयान देकर अपने हिंसात्मक सोच को उजागर किया है। भाजपा जो सरकार में है तथा एक राजनैतिक दल के रूप में राज्य की कानून व्यवस्था बनाना जिसकी संवैधानिक जवाबदारी है कि वह

अपराधी के साथ कैसे खड़े हो सकती है? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा इस मामले में अपना स्टैण्ड क्लियर करे। वे दोषी विधायक के खिलाफ कार्यवाही का साहस दिखायेंगे? मुख्यमंत्री साय, गृह मंत्री शर्मा बताये, वे संविधान के साथ है या पार्टी के असंवैधानिक निर्णय के साथ है?प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा ने अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं को अधिकारी कर्मचारियों, पत्रकारों एवं आमजनता के साथ मारपीट, गुंडागर्दी, दुर्व्यवहार, हिंसा करने की छूट दी है इसलिए प्रदेश में लगातार भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी की खबरे सामने आ रही है, जो लोकतंत्र एवं संविधान में स्वीकार नहीं है। भाजपा संगठन और सरकार गुंडागर्दी करने वाले अपने नेताओं को बचा रही है।

उर्वरक के लिये मारामारी शुरू सरकार निश्चिंत बनी हुई: शुक्ला

रायपुर। प्रदेश में उर्वरक का संकट विकराल रूप ले चुका है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में उर्वरक के लिये मारा मारी शुरू हो गयी है। किसानों को सोसायटी में खाद नहीं मिल रहा है। किसान बराबर सरकार के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों से उर्वरक के बारे में गुहार लगा रहे, लेकिन सरकार केवल जुबानी आश्वासन दे रही है। आज भी प्रदेश के तीस प्रतिशत से कम सोसायटियों में ही खाद पहुंच पाया है।

मानसून आने वाला है, खरीफ में धान की फसल ही राज्य के किसानों की आजीविका का मुख्य आधार है। यदि खरीफ के सीजन में सरकार किसानों को पर्याप्त उर्वरक नहीं दे पायेगी तो किसानों के सामने साल भर के लिये आजीविका का संकट पैदा हो जायेगा। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि खरीफ सीजन शुरू होने के पहले सरकार का दायित्व है कि वह किसानों के मांग के अनुरूप सोसायटियों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक पहुंचाएं ताकि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो सके। सरकार उर्वरकों की उपलब्धता पर श्वेत पत्र जारी करे। कृषि मंत्री स्पष्ट करें कि अभी तक सरकार के पास कितने टन उर्वरकों की मांग का अनुमान है और सरकार ने कितने टन उर्वरक इंतजाम कर लिया है।

महंगाई के चलते पीएम आवास लागत में बढ़ोतरी हो: ठाकुरे

रायपुर। महंगाई को देखते हुए पीएम आवास बनाने की राशि मे वृद्धि करने की मांग करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि स्टील, सीमेंट, रेत, इंट, गिट्टी, इलेक्ट्रिक समान, रंग-पेंट, सेनेटरी समान, दरवाजा-खिड़की, टाईल्स के दाम एवं मजदूरी में बढ़ोत्तरी होने के चलते पीएम आवास बनाने की लागत मूल्य में भारी वृद्धि हो गई है। ऐसे में पीएम आवास बनाने योजना में दी जा रही राशि से आवास बनाना कठिन हो गया

है। महंगाई के चलते पीएम आवास के हितग्राहियों के आवास के काम रुक गये है, उन्हें मोटे ब्याज में कर्ज लेकर, जेवर गिरवी रखकर आवास निर्माण पूरा कराने मजबूर हो रहे है। ऐसे में सरकार को योजना की राशि में वृद्धि कर आवास बनाने में मदद करना चाहिये। ताकि हितग्राही मजबूरी में कर्ज के जंजाल में न फंसे व अधूरा आवास बारिश के पहले पूरा हो सके। गरीबों के खुद का पक्का मकान का सपना पूरा हो सके। सरकार को इस दिशा में कड़े कदम उठाना चाहिए। अभी राज्य में हजारों पीएम आवास का निर्माण आवास योजना की समय पर किस्त नहीं मिलने एवं निर्माण सामग्री के बढ़े दाम के चलते रुका पड़ा है। आवास योजना के हितग्राही बारिश के सीजन एवं अधूरा आवास के कारण चिंतित है।

पिछले साल का धान अभी तक संग्रहण केन्द्रों में पड़ा है: वर्मा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण लगभग 20 लाख मीट्रिक टन धान संग्रहण केन्द्रों में खुले में पड़ा है। धान भीषण गर्मी में सुख रहा है, बे-मौसम बारिश से भीग रहा है। 3100 रु. प्रति क्विंटल में खरीदे गए धान का सरकार निराकरण नहीं कर पाई है। भाजपा दावा करती है डबल इंजिन की सरकार का तो केंद्र से बोल कर पूरे खरीदे गए धान से बने चावल को सेन्ट्रल पुल

में दे दे, इससे राज्य को करोड़ों का नुकसान भी नहीं होगा, धान का निराकरण का समाधान भी हो जायेगा। धान खुले में पड़ा सुख रहा है, सड़ रहा है, बाद में इसी के आधार पर पूरा धान खराब हो गया बता कर भ्रष्टाचार करेंगे। चूहों पर तोहमत लगाएंगे। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने प्रदेश की विष्णुदेव सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान से बना पूरा चावल नहीं खरीदा, जिसके चलते राज्य सरकार को किसानों से खरीदे गए धान के निस्तारण की समस्या उत्पन्न हो गई है। दलीय चाटुकारिता और मोदी-शाह के अधिनायक वाद के चलते राज्य की सरकार केंद्र पर भी दबाव नहीं बन पा रही है।

सरकार का अमानवीय चेहरा उजागर : वंदना राजपूत

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने राजनांदगांव में एक नाबालिक बच्ची के साथ पुलिस की बर्बरता एवं छत्तीसगढ़ सरकार की भ्रष्ट स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते जो अमानवीय कृत्य हुआ है वह शर्मनाक है। बच्ची ने पेट दर्द की शिकायत की लेकिन अमानक टेस्ट किट के मेडिकल टेस्ट में उसे गर्भवती बताया गया, जिससे पूरा परिवार मानसिक रूप से प्रताड़ित तो था ही वही सोमनी पुलिस ने पीड़ित बालिका को रात भर

थाने में बिठाकर उससे अमानवीय प्रश्न पूछ कर मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का जो कार्य किया, क्योंकि सोमनी स्वास्थ्य केंद्र द्वारा जिस किट से बच्ची के टेस्ट किए गए उस टेस्ट किट में बच्ची को गर्भवती बताया गया उसके पश्चात अन्य मेडिकल टेस्ट पर उसे गर्भवती नहीं बताया गया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि सोमनी स्वास्थ्य केंद्र के टेस्ट किट जो स्थानीय स्तर पर क्रय की गई थी, वह अमानक और नकली भी उसमें रिपोर्ट गलत आई थी। छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य जैसे मामलों में भी फर्जीवाड़ा करने से नहीं चूक रही है। लगातार नकली दवाइयां सप्लाई का मामला पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के संरक्षण में हो रहा है।

शहीदी दिवस पर गुरुद्वारा तेलीबांधा में आयोजित विशाल छबील एवं छायाचित्र प्रदर्शनी में हुए शामिल

गुरु अर्जुन देव ने दिया सेवा और मानवता का संदेश

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के तेलीबांधा स्थित गुरुद्वारा परिसर में छत्तीसगढ़ सिक्ख समाज द्वारा आयोजित विशाल छबील एवं छायाचित्र प्रदर्शनी में शामिल होकर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया और उनके महान बलिदान को मानवता, सत्य तथा सेवा की रक्षा का अमर संदेश बताया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने राहगीरों को शरबत एवं प्रसादी वितरित कर सेवा परंपरा में सहभागी बनते हुए समाज को परोपकार, संवेदना और मानवीय मूल्यों का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान सिक्ख समाज ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर आत्मीय स्वागत किया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुद्वारा परिसर में आयोजित गुरु अर्जुन देव जी के जीवन पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदर्शनी में उनके दिव्य जन्म से लेकर शहादत तक की प्रेरक और गौरवपूर्ण यात्रा को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया गया था। इसमें गुरु गद्दी की प्राप्ति, हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा के निर्माण, आदि ग्रंथ साहिब के संकलन, जहांगीर से वैचारिक संघर्ष, गिरफ्तारी, असहनीय यातनाओं के बीच अडिग आस्था का विस्तृत चित्रण शामिल था।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गुरु अर्जुन देव जी त्याग, तपस्या, सत्य, सेवा और मानवता की महान प्रतिमूर्ति थे। उनका संपूर्ण जीवन समाज को प्रेम, समानता, करुणा, समर्पण और मानव कल्याण का मार्ग दिखाता है। उन्होंने कहा कि गुरु अर्जुन देव जी ने अन्याय, अत्याचार और दमन के सामने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। असहनीय यातनाओं के बावजूद उनका धैर्य, साहस, आत्मबल और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास आज भी संपूर्ण मानवता के लिए अमर प्रेरणा का स्रोत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदी दिवस पर आयोजित 'छबील सेवा' केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि सेवा, करुणा, भाईचारे और मानवता की जीवंत अभिव्यक्ति है। भीषण गर्मी के बीच राहगीरों को ठंडा और मीठा शरबत पिलाना निस्वार्थ मानव सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सिक्ख परंपरा में छबील सेवा मानवता के प्रति समर्पण, सह-अस्तित्व और परोपकार की भावना को जीवंत बनाए रखने का माध्यम रही है।

तंबाकू मुक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण में सभी की भागीदारी जरूरी: राजवाड़े

रायपुर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेशवासियों से तंबाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि तंबाकू सेवन व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और समाज तीनों के लिए गंभीर खतरा है।

समाज कल्याण मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने अपने संदेश में कहा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने का महत्वपूर्ण अवसर है। तंबाकू के सेवन से कैंसर, हृदय रोग, श्वसन संबंधी बीमारियों सहित कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न

होती हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर कार्य करना होगा।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नशा मुक्ति अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। स्कूलों, महाविद्यालयों तथा ग्राम पंचायतों में विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि स्वस्थ, जागरूक और नशामुक्त समाज का निर्माण किया जा सके।

समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने युवाओं से सकारात्मक सोच एवं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आह्वान करते हुए कहा कि नशे से दूरी ही सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी कुंजी है। उन्होंने सभी नागरिकों से तंबाकू मुक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.